वर्ष : 34 | अंक : 266 | मुंबई, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD
दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव

मतगणना पर रोक

- 3 दिसंबर को नहीं होगी महाराष्ट्र निकाय चुनावों की मतगणना
- निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट का फरमान
- 30 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा : सीएम फडणवीस

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है इसके मुताबिक अब निकाय चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले तक यानी 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल भी नहीं किया जाएगा। गौरतलब हो कि निकाय चुनावों के पहले चरण में मंगलवार को वोट डाले गए थे। इनमें राज्य नगर पंचायत और नगर परिषद शामिल हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग से ठीक दो दिन पहले 24 स्थानीय निकायों में वोटिंग की तारीख बदल दी थी। आयोग के इस फैसले से यहां चुनाव टल गए थे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतगणना की नई तारीख तय कर दी है। इस फैसले की वजह यह ही कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे आते, तो 24 स्थानीय निकाय जहां पर वोटिंग 20 को होगी, वहां के मतदाता प्रभावित हो सकते थे।

21 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित

याचिकाकर्ताओं में से एक सामाजिक कार्यकर्ता सचिन चुटे ने अनुरोध किया कि परिणामों की घोषणा एक ही तिथि पर की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग। याचिका में दावा किया गया कि निर्वाचन आयोग के आदेश ने इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष होने चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। चुटे के अधिवक्ता यश कुल्लरवार ने तर्क दिया कि सभी वार्ड के परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने बताया कि हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट एसईसी के संशोधित चुनाव कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा।

'सांविधानिक और स्वतंत्र संस्थाओं के आदेश का पालन होना चाहिए'

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अदालत के इस फैसले के बाद कहा, राज्य के 24 अन्य निकायों में चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए गए हैं। केवल इस आधार पर मतगणना को टालना ठीक नहीं। उन्होंने एक बार फिर उस फैसले की आलोचना की, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 24 निकायों में चुनाव टाल दिया। निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, आयोग ने कानून की गलत व्याख्या की है।

288 अध्यक्षों के भाग्य का फैसला बक्से में बंद

- मतदान समाप्त, कई जगह फर्जी मतदान को लेकर विरोध प्रदर्शन

मुंबई। राज्य में 226 नगर परिषदों और 38 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर कई जगहों पर भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं। सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी में भाजपा और शिवसेना के बीच हाथापाई देखने को मिली। मतदान से कुछ ही मिनट पहले भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई।

महाड में विकास गोगावले-सुशांत जाबरे समर्थक भिड़े

रायगढ़ के महाड में विकास गोगावले और सुशांत जबारे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ऐसी खबरें हैं कि एनसीपी नेता जबारे की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जाबरे कुछ दिन पहले ही शिंदे सेना छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। महाड में बूथ सेंटर का निरीक्षण करने के दौरान यह झड़प हुई।

मनमाड में झड़पें

नासिक जिले के मनमाड में भी अफरा-तफरी मच गई। यहाँ भाजपा और शिंदे सेना कार्यकर्ताओं के बीच बहस छिड़ गई। मतदान में बस एक घंटा बाकी था, तभी भाजपा उम्मीदवारों के रिश्तेदारों ने एक मतदान केंद्र पर कुछ महिलाओं के अवैध रूप से मतदान करने पर आपत्ति जताई। दोनों गुट आमने-सामने आ गए और हाथापाई हो गई। धुले के पिंपलनेर नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान के दौरान भाजपा और शिंदे सेना कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ कार्यकर्ता वार्ड क्रमांक 4 स्थित मतदान केंद्र में घुस गए।

ब्रीफ न्यूज़

एनआईए ने 2008 से अब तक दर्ज किए 692 केस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत 26/11 के मुंबई हमलों के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में की गई थी। एनआईए की स्थापना के बाद से लेकर अभी तक 692 केस दर्ज किए गए हैं। 172 मामलों में सुनाए गए निर्णयों में दोषसिद्धि दर 92.44 प्रतिशत रही है। एनआईए अब एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित जाँच एजेंसी के रूप में उभरी है। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए विभिन्न संगठनों के विरुद्ध निरंतर और कड़ी कार्रवाई की है। पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने 23 संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित किया है।

कफ सिरप कांड के बाद केंद्र सरकार ने बढ़ाई सख्ती

नई दिल्ली। बच्चों की मौत के मामलों में खांसी की दूषित दवा (कफ सिरप) को जिम्मेदार समझे जाने के बाद सरकार ने देशभर में कार्रवाई तेज कर दी है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 700 से अधिक खांसी की दवा बनाने वाली कंपनियों की सख्त जांच और ऑडिट किया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखित जवाब में कहा कि बच्चों की संदिग्ध मौतों की सूचना मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई।

कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में बम की धमकी निकली झूठी

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो के कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में बम की धमकी की सूचना जांच के बाद झूठी साबित हुई है। हालांकि इस मामले में बम की धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रोसीजर फॉलो किए गए। सिक्योरिटी एजेंसियों के एयरक्राफ्ट की जांच शुरू करने से पहले पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया।

महाराष्ट्र में चल रही 'उलेमा फैक्ट्री'

- 1100 करोड़ का विदेशी चंदा मिला
- बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया आरोप

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देशभर में आतंकी नेटवर्क की छानबीन तेज है। इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद की विवादों में घिरी अल फलाह यूनिवर्सिटी की तर्ज पर महाराष्ट्र के अक्कलकुवा में भी एक संगठन सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम नामक संस्था को विदेश से 1100 करोड़ रुपये का फंड मिला है और यहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर से आए छात्र पढ़ रहे हैं, जिन्हें कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की साजिश चल रही है।

विदेशी फंडिंग का आरोप

सोमैया ने दावा किया कि महाराष्ट्र के इस संगठन में 11,200 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल के मालदा और बॉर्डर इलाके से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां "उलेमा तैयार करने के लिए फैक्ट्रियां" चलाई जा रही हैं और छात्रों को कट्टर विचारधारा सिखाई जा रही है। इस संस्था को विदेशों से 1100 करोड़ रुपये के डोनेशन मिलने का आरोप भी लगाया गया।

ED और केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी

बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहां कैसे पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और अब ED ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई स्थानों पर छापेमारी भी हुई है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार पर भी उठे सवाल

सोमैया के अनुसार यह संस्था काफी पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन हथिया कर जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर गतिविधियां चलाई जा रही हैं। दावा किया कि संगठन को जिहादी नेटवर्क से जुड़े समूहों को फंड भेजने के भी आरोपों की जांच की जा रही है। ATS ने भी इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है।

यूनिवर्सिटी से जुड़ी कड़ियां और पुराने खुलासे

किरिट सोमैया ने यह भी कहा कि संस्था को मिडिल ईस्ट के टैक्स हेवन देशों से पैसा मिला है और भारत की कई बेनामी संस्थाओं से भी फंड आया है, जिनके पांच नाम उन्होंने सरकार को सौंपे हैं। बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके का आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का प्रोफेसर था।

ठंड से ठिठुरता महाराष्ट्र

- मुंबई का भी पारा लुढ़का

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र ठंड से ठिठुर रहा है। इस बीच मुंबई में न्यूनतम तापमान 20C तक गिर गया है, जबकि कोकण में यह 16–19C के बीच दर्ज किया गया है। मुंबई में 3 दिसंबर को साफ और शुष्क दिन रहने की उम्मीद है। सुबह का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो दोपहर तक बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई में किसी भी मौसम चेतावनी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को शीतलहर के लिए येलो अलर्ट पर रखा गया है। अगले 48 घंटों में धुले, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, अहिल्यनगर और पुणे जिलों में न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। पिछले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पहले जहां तापमान 15-18 डिग्री तक था, अब वह 9 डिग्री तक पहुँच गया है। विदर्भ और मराठवाडा में ठंड की लहर के कारण लोग सुबह-सुबह धुंध और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं।

बीएमसी अधिकारी बनकर उगाही करने वाला गिरोह बेनकाब

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

धारावी में छोटे कारोबारियों को निशाना बनाकर खुद को बीएमसी का अधिकारी बताने वाले फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी हनुमंता नागप्पा कुर्चिकुर्वे को गिरफ्तार किया है, जबकि दो महिलाएं और एक अन्य शख्स अभी फरार हैं। मामला तब सामने आया जब राजीव गांधी नगर में बैग बनाने वाले 35 वर्षीय अबिद बिगना शेख ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

छोटे कारोबारियों से पैसों की उगाही

शेख के मुताबिक, उनकी फैक्ट्री अंबेडकर चॉल के पहले माले पर थी। उसी दौरान दो महिलाएं, दीपाली दीपक दलवी और मेघा सोनवणे, फैक्ट्री पहुंचीं और खुद को बीएमसी कर्मचारियों के रूप में पेश किया। बच्चों को देखकर उन्होंने बाल श्रम का मामला दर्ज कराने की धमकी दी और मौके पर ही 25,000 वसूल लिए। बाद में दीपाली दलवी अपने साथी हनुमंता नागप्पा कुर्चिकुर्वे के साथ "सेटलमेंट" के नाम पर फिर से पैसे मांगने गई।

पुलिस कार्रवाई और मामले की जांच

धारावी पुलिस की डिटेक्शन टीम ने हनुमंता कुर्चिकुर्वे को उसके ट्रांजिट कैंप के घर से गिरफ्तार किया। शेख की शिकायत पर पुलिस ने दीपाली दीपक दलवी, मेघा सोनवणे, हनुमंता नागप्पा कुर्चिकुर्वे और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और उगाही के मामले दर्ज किए हैं।

सांस्कृतिक बदलाव...

एजेंसी | नई दिल्ली

- प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ
- केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन और राजभवन अब लोकभवन कहलाएंगे
- सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे : पीएमओ

एक युग का अंत, एक नए युग की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से भारत के नक्शे पर राजशाही के आखिरी प्रतीक भी मिट गए। अब देश के हर राज्य में गवर्नर हाउस नहीं, बल्कि जनता का अपना लोकभवन होगा। और दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च केंद्र, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम है- सेवा तीर्थ। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। नाम ही बता रहा है कि यह भवन अब सत्ता के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प का प्रतीक बनेगा।पीएमओ के अफसरों ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है।

क्यों बदला गया राज भवन का नाम?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राज भवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए राज्यपालों और उप-राज्यपालों के कार्यालयों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक स्पष्ट और गहरा संदेश है कि सत्ता कोई सुख भोगने या विशेषाधिकार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का नाम है। नाम बदलना सिर्फ प्रतीकात्मक कदम या दिखावा नहीं है, इसके पीछे एक सोचा-समझा विचार और संदेश छिपा है। संदेश यह है कि शासक का काम जनता की सेवा करना है, न कि सत्ता के ऐश्वर्य में डूबना।

पहले भी बदले गए हैं नाम

दरअसल, मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में अनेक स्थानों, सड़कों और संस्थानों के नाम बदले गए हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण राजपथ का है, जिसका नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' कर दिया गया। दरअसल, राजपथ शब्द में राजशाही और शक्ति का बोध था, जबकि कर्तव्य पथ स्पष्ट रूप से बताता है कि सत्ता कोई अधिकार या विलासिता नहीं, बल्कि कर्तव्य और जन-सेवा का मार्ग है। 2016 में रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर 'लोक कल्याण मार्ग' किया गया। बता दें कि रेसकोर्स नाम कुलीन वर्ग की मस्ती और घुड़दौड़ का प्रतीक था, जबकि लोक कल्याण मार्ग सीधे-सीधे जनता को यह संदेश देता है कि प्रधानमंत्री का निवास स्थान भी अब जनकल्याण का केंद्र है, न कि किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या विलासिता का प्रतीक।

पूर्व सीएम येदियुरप्पा को राहत

- पॉक्सो मामले में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे पोक्सो मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने येदियुरप्पा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मामले को रद्द करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

'अदालत ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया'

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'नोटिस जारी करें। इस बीच, ट्रायल पर रोक रहेगी।' पीठ ने कहा कि नोटिस मुख्य रूप से मामले को हाई कोर्ट को वापस भेजने पर विचार करने के लिए जारी किया जा रहा है। येदियुरप्पा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया और उन बयानों पर विचार नहीं किया।

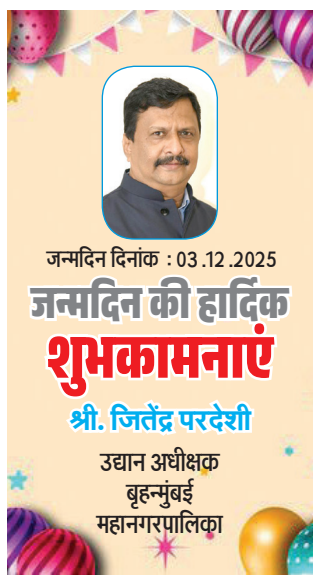

डीआरडीओ पायलट को बचाने वाले स्वदेशी 'एस्केप सिस्टम' का सफल परीक्षण

सैन्य क्षेत्र में भारत ने रचा आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान

एजेंसी | नई दिल्ली

सैन्य क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लड़ाकू विमान के स्केप सिस्टम का एक सफल उच्च-गति रॉकेट-स्लेड परीक्षण किया है, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दी। स्वदेशी फाइटर जेट की सुरक्षा तकनीक के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस परीक्षण का एक वीडियो साझा किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह टेस्ट चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में 800 किमी/घंटे कंट्रोल्ड स्पीड पर किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल हो गया है, जिनके पास पायलट इजेक्ट सिस्मट की यह जटिल प्राणाली है। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लड़ाकू विमानों से बाहर निकलने के लिए विकसित एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च-गति रॉकेट-स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

इन संस्थाओं ने मिलकर किया परीक्षण

यह परीक्षण एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सहयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। यह अत्यंत जटिल और गतिशील परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करता है, जिनके पास उन्नत इन-हाउस एस्केप सिस्टम के पूर्ण परीक्षण की क्षमता उपलब्ध है। गतिशील इजेक्शन परीक्षण, नेट टेस्ट या जीरो-जीरो टेस्ट जैसे स्थैतिक परीक्षणों की तुलना में कहीं अधिक जटिल होते हैं और इजेक्शन सीट के समग्र प्रदर्शन तथा कैनोपी सेवरेंस सिस्टम की वास्तविक प्रभावकारिता का सबसे विश्वसनीय मानक माने जाते हैं।

ब्रह्मोस बनाने वाली टीम के इंजीनियर निशांत अग्रवाल बरी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को बरी कर दिया है। इनपर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप था। अक्टूबर 2018 में निशांत को गिरफ्तार किया गया था। फिर बाद में 3 जून 2024 को नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्रकैद (14 साल) की सजा सुनाई थी। जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच में सामने आया था कि निशांत कोड गेम्स के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारी ISI को भेजा करता था। निशांत ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के नागपुर स्थित मिसाइल सेंटर के टेक्निकल रिसर्च सेंटर में काम करता था। यहां उसने चार साल काम किया।

न्यूज ब्रीफ

प्रजा फाउंडेशन ने नागरिक घोषणापत्र जारी किया

मुंबई: आगामी बीएमसी चुनावों से पहले, गैर सरकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चुनाव 2025 के लिए अपना नागरिक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें शहरी शासन को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधारों की रूपरेखा दी गई है। घोषणापत्र में बेहतर सेवा वितरण, पारदर्शी और सुलभ नागरिक डेटा और नगरपालिका कर्मचारियों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अगले दो हफ्तों में, यह एनजीओ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से मिलकर इस नागरिक-संचालित एजेंडे को प्रस्तुत करेगा और इसे अपने चुनावी मंचों में शामिल करने की वकालत करेगा।

मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए नगरपालिका वार्डों में हेल्प डेस्क

कल्याण : आगामी नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में, कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने नागरिकों की जानकारी के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशित किया है। इन सूचियों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। इस संबंध में नगर पालिका नागरिकों से आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त कर रही है। राजनीतिक हलकों और नागरिकों के बीच मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति को कम करने के लिए, कल्याण डोंबिवली नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका की वेबसाइट पर एक सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि नागरिक घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देख सकें। साथ ही, नगर निगम मुख्यालय और वार्ड कार्यालयों में सहायता कक्ष शुरू किए गए हैं।

कुलगांव बदलापुर नगर परिषद चुनाव में औसतन 60% मतदान

बदलापुर: मंगलवार को साढ़े दस साल के अंतराल के बाद हुए कुलगांव बदलापुर नगर परिषद चुनाव में औसतन 60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे तक 58 प्रतिशत मतदान हुआ था। देर रात तक सभी मतदान केंद्रों से आंकड़े जुटाए जा रहे थे, लेकिन अंतिम मतदान प्रतिशत देर रात तक सामने नहीं आ सका। चर्चा रही कि तीन वोट डालने में हुई देरी से मतदान प्रतिशत में गिरावट आई। चुनाव के दिन सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। कई केंद्रों पर वोटिंग मशीनें खराब होने के कारण मतदाता मतदान करने में देरी का सामना कर रहे थे। इस वर्ष दो सदस्यीय वार्ड प्रणाली और सीधे मेयर चुनाव के कारण मतदाताओं को एक साथ तीन वोट डालने पड़े। हालांकि चुनाव अधिकारियों और प्रशासन ने इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की थी, लेकिन कई मतदाताओं को तीन वोट डालने का गणित समझ नहीं आया। नतीजतन, तीन वोट डालने में अधिक समय लगने के कारण बाहर कतारें लंबी होती गईं।

युवती के यौन उत्पीड़न के आरोप में जिम मालिक गिरफ्तार

कल्याण। कल्याण में जिम आने वाली 29 वर्षीय युवती से दोस्ती बढ़ाकर उसे प्रेमजाल में फँसाने और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में जिम मालिक विनीत गायकर (34) को खड़कपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जब विनीत ने उसके मोबाइल फोन को हैक कर उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी। पीड़िता अपने परिवार के साथ कल्याण पश्चिम में रहती है और फिटनेस के लिए नियमित रूप से विनीत के जिम में जाती थी।

सत्ताधारी पक्षों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

नगरपालिका चुनावों में भाजपा महायुती सहित सत्ताधारी दलों पर सभी नियमों को दरकिनार करते हुए आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की खुलेआम अवमानना की गई। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में गैरकानूनी गतिविधियों की 25 नहीं, बल्कि 25 हजार से अधिक शिकायतें हुईं, लेकिन चुनाव आयोग तक कितनी पहुँचीं—यह गंभीर सवाल है।

पैसे का खेल, दबदबा और फर्जी वोटिंग के आरोप

पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान सपकाळ ने कहा कि नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में हर जगह पैसे का बेहिसाब इस्तेमाल, दादागिरी, दबाव और फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी देखी गई। भाजपा, शिंदे सेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सभी नियमों को पैरों तले रौंदने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी महायुती ने लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को भारी नुकसान पहुँचाया।

कांग्रेस के 165 नगराध्यक्ष पदों पर दावेदारी

इस सवाल पर कि चुनाव में कांग्रेस दिखाई क्यों नहीं दी, सपकाळ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने "पंजा" चुनाव चिन्ह पर 165 नगराध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। वे स्वयं राज्यभर में 65 से अधिक प्रचार सभाएँ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दलों के नगराध्यक्ष और नगरसेवक जीत भी जाएँ, तो भी सत्ताधारी दल उन्हें तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। असली चिंता यह है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

'भाजपा में रावण से भी अधिक अहंकार'

छत्रपति शिवाजी महाराज को भाजपा की टोपी और गमछा पहनाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाळ ने कहा कि भाजपा और उसके नेता खुद को महापुरुषों और देवताओं से भी ऊपर समझने लगे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा को रावण से भी अधिक घमंड हो गया है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए खतरनाक संकेत है।

'19 साल के हो, शादी के लिए 21 तक रुको'

नाराज युवक ने इंतजार वाली बात पर दे दी जान

डीबीडी संवाददाता । डोंबिवली

डोंबिवली में 19 वर्षीय युवक ने परिवार की मना करने पर एक लड़की से शादी करने की इच्छा पूरी न होने के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घटना 30 नवंबर 2025 को हुई। युवक ने अपने घर की छत पर दुपट्टे से फांसी लगाई। परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का परिवार उसे यह कहकर मना कर रहा था कि वह अभी 19 साल का है और 21 साल की उम्र तक शादी के लिए इंतजार करे। युवक को यह बात बुरी लगी और उसने आहत होकर यह कदम उठाया। मामला प्रेम और सामाजिक दबाव के बीच युवाओं की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

मामला दुर्घटना के रूप में दर्ज

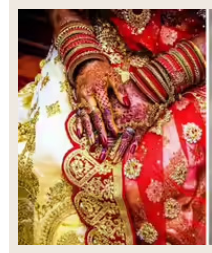

पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना के रूप में दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई कि युवक डोंबिवली इलाके का निवासी था और झारखंड मूल का परिवार इस घटना से जुड़ा है। मनपाड़ा पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रहा है।

ठाणे मनपा प्रभागों में 10,000 फर्जी मतदाता

पूर्व सांसद राजन विचारे ने किया दावा

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

उद्धव बालठाकरे गुट के शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे ने ठाणे नगर निगम चुनाव के लिए हाल ही में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गंभीर गलतियों का खुलासा किया है। उनका कहना है कि ठाणे नगर निगम क्षेत्र में 10,653 फर्जी मतदाता हैं, 6,649 सिंगल नाम वाले वोटर हैं और 3,485 वोटरों की लिस्ट में केवल पहला और आखिरी नाम ही दर्ज है।

डुप्लीकेट और गलत मतदाता विवरण

राजन विचारे ने बताया कि ठाणे नगर निगम क्षेत्र की 33 वार्डों में डुप्लीकेट और गलत वोटर विवरण सामने आए हैं। 1,575 वोटर जिनके पास एपिक ID थी, लेकिन सूची में नहीं थे। दो वार्डों में एक ही नाम वाले 6,649 वोटर पाए गए। कुछ वोटरों की उम्र 100 साल से ऊपर दिखाई गई, जबकि वास्तविक उम्र कम थी। वहीं 21 मृत वोटरों के नाम भी सूची में मौजूद हैं और कई नाम अन्य वार्ड से शामिल किए गए हैं।

वोटर लिस्ट में समय और प्रक्रिया की कमियाँ

पूर्व सांसद राजन विचारे ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 20 नवंबर को प्रकाशित हुई थी और आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय थी। हालांकि, उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट जमा करने में देरी हुई। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर तक आपत्तियाँ स्वीकार करने का निर्णय लिया। जब वे सभी वार्डों की लिस्ट इकट्ठा करने गए, तो लिस्ट कम्पाइलेशन बुक में बंडल की गई थी। इसे तोड़ने और मिलाकर तैयार करने में 2–3 दिन लगे, जिससे कार्य करते समय कई समस्याएँ सामने आईं।

लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया के लिए गंभीर संकेत

राजन विचारे ने चेतावनी दी कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ये नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल होने की संभावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं और तत्काल सुधार आवश्यक हैं।

सरकार, टीएमसी और एमएमआरडीए को नोटिस

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में सड़कों पर गड्ढों और अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से हुई 18 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार, ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह कदम उठाया, जबकि इसी सुनवाई में केडीएमसी ने बताया कि डोंबिवली के खुले मैनहोल में गिरकर मारे गए 13 वर्षीय बच्चे के पिता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने मुआवजा दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया।

रास्ते पर गड्ढों और अधूरे कंस्ट्रक्शन से 18 लोगों की गई थी जान
हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस, सड़क हादसों पर मांगा जवाब

डोंबिवली में बच्चे की मौत पर दो सप्ताह में मुआवजा देने का आदेश

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की पीठ के समक्ष वकील रुजू ठक्कर की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। टीएमसी के वकील ने बताया कि टीएमसी की जांच समिति ने दावाचीपाड़ा, डोंबिवली (प.) में 28 सितंबर को खुले मैनहोल में गिरकर हुई आयुष कदम की मौत के मामले में उसके पिता एकनाथ कदम को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है। पीठ ने मुआवजा जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को देने और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

ठाणे में 18 मौतों का मामला भी अदालत के संज्ञान में

सुनवाई के दौरान वकील रुजू ठक्कर ने अदालत को बताया कि ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढों और अधूरे निर्माण के चलते हाल ही में 18 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में नागरिकों ने कासरवडवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने और मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'मुंबई उच्च न्यायालय' किया जाए: विधायक सुनील प्रभु

नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में विशेष प्रस्ताव लाने की मांग
विधायक सुनील प्रभु ने मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को लिखा पत्र

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर "मुंबई उच्च न्यायालय" किए जाने की मांग दिंडोशी के शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने राज्य सरकार के समक्ष पत्र के माध्यम से रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील को भेजे पत्र में आग्रह किया है कि आगामी नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में इस संबंध में एक विशेष सरकारी प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।

8 दिसंबर को विशेष सरकारी प्रस्ताव लाने की मांग

सुनील प्रभु ने पत्र में आग्रह किया है कि 8 दिसंबर को नागपुर में आरंभ होने वाले शीतकालीन अधिवेशन में इस विषय पर विशेष सरकारी प्रस्ताव पेश किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से मंजूर कर तुरंत केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए,ताकि नामांतरण पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू हो सके।

सरकार की निष्क्रियता पर सवाल

अपने पत्र में प्रभु ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के नामांतरण पर अब तक कोई प्रभावी कदम न उठाया जाना खेदजनक है। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था और मराठी भाषा के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय व्यापक संघर्ष तथा सातत्यपूर्ण प्रयासों के बाद ही संभव हुआ। इसी प्रकार, अन्य कई प्रस्ताव भी विधानमंडल में पारित होकर सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर मुंबई उच्च न्यायालय करना ही प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप सही कदम होगा।

20 वर्षों से लंबित है नामांतरण का मामला

विधायक प्रभु ने पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले बीस वर्षों से बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर "मुंबई उच्च न्यायालय" करने की मांग विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जा रही है, परंतु अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण नामांतरण का प्रश्न आज भी लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को हाईकोर्ट पेटेंट 1862 के अनुसार आवश्यक संशोधन करना होगा, और इसी दिशा में महाराष्ट्र सरकार को ठोस पहल कर केंद्र का ध्यान आकृष्ट करणे आवश्यक है।

धोखादायक साबित हो रहा है स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर उड़ान पुल

डीबीडी संवाददाता । बदलापुर

बदलापुर रेलवे लाइन के ऊपर पूर्व-पश्चिम दिशा को जोड़ने वाला स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर उड़ान पुल अब अपनी मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहा है। वर्ष 2004 में मात्र 5 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल बीते 20 वर्षों में डामरीकरण (डामर) पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, फिर भी इसकी स्थिति अब जोखिम भरी बताई जा रही है।

लगातार डामर की परतों से कमजोर हुई संरचना

समाजसेवक ज्ञानेश्वर (नाना) देशमुख ने बताया कि पुल पर हर साल दो-तीन बार डामर का काम किया जाता रहा है। औसतन हर वर्ष करीब 10 इंच मोटी डामर की परत चढ़ाई गई, जिससे पुल का वजन जरूरत से अधिक बढ़ गया और उसकी संरचनात्मक क्षमता कमजोर पड़ गई। पुल मूल रूप से पूर्व-पश्चिम वाहनों के लिए बनाया गया था और इसका नाम विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया था।

VJTI की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए

वर्ष 2022 में VJTI की स्ट्रक्चरल टीम ने पुल की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि पुल के बीच विस्तार (एक्सपैंशन) के लिए छोड़े गए अंतर को नगर पालिका के तत्कालीन अभियंता और ठेकेदार की लापरवाही के कारण नजरअंदाज किया गया। पुराने डामर को हटाए बिना नया डामर डालने से पुल की उम्र और संरचनात्मक क्षमता पर गंभीर असर पड़ा।

राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग

देशमुख ने पुल की बदहाली पर बदलापुर के राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी दोषी ठहराया। उन्होंने नगर पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी और शहर अभियंता से VJTI रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं किया गया, तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा पर प्रशासन की सख्ती

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का एक अनिवार्य चरण है, और सटीक मतदाता सूची के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मतदाता सूची के मसौदे पर आपत्तियों और सुझावों की अंतिम तारीख 3 दिसंबर है। हाल ही में जिला कांग्रेस ने मनपा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त/प्रशासक राधाबिनोद शर्मा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। इसी के तहत आयुक्त ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ इंद्रलोक और हाटकेश स्थित कुछ आवासीय संकुलों का अचानक निरीक्षण किया, स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याएँ सुनीं, दी गई जानकारी का सत्यापन किया और संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

नागरिकों को सहायता के उद्देश्य से निरीक्षण दौरा

उपायुक्त सचिन बांगर ने कहा कि एमबीएमसी द्वारा नागरिकों को अपनी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह दौरा किया गया। मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करने और किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधारने का अवसर उपलब्ध कराना था।अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत, उपायुक्त कविता बोरकर, निगम सचिव दिनेश कानगुडे, शाखा अभियंता विकास परब सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस दौरे में उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई की मांग

जिला कांग्रेस प्रवक्ता रवि खरात ने बताया कि उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने शनिवार और रविवार को अधिकारियों को उपस्थित रहकर आपत्तियों का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद प्रभाग 4 के अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद तेज

एमबीएमसी ने शुरू किया धूल नियंत्रण अभियान

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मीरा-भाईंदर शहर में बढ़ते प्रदूषण से परेशान नागरिकों को राहत देने और वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एमबीएमसी ने धूल नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। प्रशासन शहर में बढ़ते धूल स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय अपना रहा है। पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए धूल नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर धूल कम करने और वायु गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

> "शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशासन निरंतर प्रयासरत है, और आने वाले दिनों में जल छिड़काव, स्वच्छता अभियान एवं अन्य धूल नियंत्रण उपाय नियमित रूप से जारी रहेंगे।
> सचिन बांगर, उपायुक्त

मुख्य मार्गों व वार्डों में व्यापक जल छिड़काव, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती

1 दिसंबर से शुरू अभियान के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से फाउंटेन और गायमुख क्षेत्र तक मनपा की धूल नियंत्रण मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव किया गया। भारी यातायात, सड़क निर्माण और शुष्क वातावरण के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद 2 दिसंबर को प्रभाग क्रमांक 03, 04, 05 और 06 में भी धूल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर जल छिड़काव किया गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख सड़कों और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में धूल कणों की मात्रा को नियंत्रित करना था।

'यह इलेक्शन नहीं, सलेक्शन चल रहा है'

चुनाव आयोग पर आदित्य ठाकरे का हमला

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए 20 नवंबर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष पहले ही राज्य चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज करा चुका है और सूची को पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर रहा है। शिवसेना (उद्धव) विधायक आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वे स्वयं शाखाओं में जाकर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। कई जगह धमकियों और पैसों के दुरुपयोग की जानकारी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया चुनाव नहीं बल्कि 'सलेक्शन' की तैयारी जैसी दिखाई दे रही है।

प्रारूप मतदाता सूची में सामने आई बड़ी विसंगतियाँ

विपक्ष के अनुसार मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। लगभग 14 लाख डुप्लीकेट नाम दर्ज पाए गए जबकि आयोग 11 लाख बता रहा है। कई वार्डों में 3-4 हजार आपत्तियाँ दर्ज हो चुकी हैं। मृत मतदाताओं के नाम हटाए नहीं गए और कई बड़े नेताओं के नाम 7-8 बार सूची में मौजूद हैं। वहीं 33 हजार नए नाम गलत तरीके से जोड़े जाने का दावा किया गया है।

बीएलओ की योग्यता पर भी सवाल

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कई बीएलओ अपात्र हैं, जिनमें कुछ पढ़ना-लिखना भी ठीक से नहीं जानते। ऐसे कर्मचारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने से प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। मराठी मतदाताओं के नामों में सबसे अधिक डुप्लीकेशन मिलने से राजनीतिक साजिश की आशंका जताई जा रही है।

आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग

विपक्षी दलों ने कहा कि डुप्लीकेट और गलत प्रविष्टियों की संख्या इतनी अधिक है कि निर्धारित अवधि में जांच पूरी करना संभव नहीं है। इसलिए आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए कम से कम 7 दिन और बढ़ाने की माँग की गई है, ताकि वास्तविक मतदाता अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

शौर्य पाटिल आत्महत्या मामला

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने पुलिस आयुक्त को कार्रवाई का दिया निर्देश

डीबीडी संवाददाता । मुंबई/नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी स्थित सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य पाटिल की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के सेंट्रल दिल्ली डीसीपी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की यह कार्रवाई सांगली के अधिवक्ता विश्राम अशोकराव कदम की शिकायत के जवाब में की गई है।

एनसीपीसीआर ने बताया कि वह इस मामले में संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगेगा। उल्लेखनीय है कि सेंट कोलंबस स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्र शौर्य पाटिल ने 18 नवंबर को प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान होकर राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

चैत्यभूमि में सुरक्षा और सेवा सुविधाओं को सख्ती से लागू करने के निर्देश

इंदु मिल में मूर्ति को लेकर बनाई जाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महापरिनिर्वाण दिवस पर देशभर से लाखों अनुयायियों के मुंबई पहुंचने को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चैत्यभूमि पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की लगने वाली नई मूर्ति को लेकर मिले सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। फडणवीस ने बाबासाहेब के विचारों को आगे बढ़ाने की अपील भी की।

तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक

सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, पूर्व मंत्री विजय गिरकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगरानी, कोंकण आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, बेस्ट की महाप्रबंधक सोनिया सेठी, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों—सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, परिवहन और भीड़ प्रबंधन—का विस्तार से आकलन किया गया।

सुविधाओं व ट्रैफिक प्लानिंग पर विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि चैत्यभूमि क्षेत्र में मंडप, पानी, टॉयलेट और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था उचित रूप से की जाए। दादर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस को सुचारू यातायात सुनिश्चित करना होगा, साथ ही सूचना बोर्ड और BEST की अतिरिक्त बस सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में वाटरप्रूफ पवेलियन, सीसीटीवी कैमरे, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस का आधिकारिक पोस्टर और सूचना पुस्तिका का अनावरण भी किया गया।

रामी ग्रुप ऑफ होटल्स के 38 ठिकानों पर आयकर का छापा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

आयकर विभाग (आईटी) की टीम मंगलवार सुबह से मुंबई समेत देशभर के 10 शहरों में रामी ग्रुप ऑफ़ होटल्स से जुड़े 38 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि आईटी की टीम रामी ग्रुप आफ होटल्स के सांताक्रुज स्थित मुख्यालय और दादर पूर्व स्थित होटल के साथ ग्रुप के मालिक के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई कर चोरी के सिलसिले में की जा रही है। मुंबई सहित देशभर के 10 शहरों के कुल 38 ठिकानों पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। इसके अलावा वरदराज मंजप्पा शेट्टी से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई।

रामी होटल ग्रुप पर पहले भी हो चुकी है रेड

यह पहली बार नहीं है जब रामी होटल ग्रुप पर इस तरह की रेड पड़ी है। इससे पहले जून 2019 में, माटुंगा पुलिस ने दादर ईस्ट में रामी गेस्टलाइन होटल पर रेड मारी थी। उन्होंने इस होटल की सातवीं मंज़िल पर रेड मारी थी। खबर मिली थी कि वहां क्रिकेट बेटिंग रैकेट चलाया जा रहा था। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर भी शामिल था। इससे पहले 2012 में, खार में रामी गेस्टलाइन होटल के डिस्कोथेक 'मैडनेस' पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने होटल के तय समय से ज्यादा खुले रहने पर रेड मारी थी और एक प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में दस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और 16 लड़कियों को बचाया गया था।

कई देशों में फैला है बिजनेस

रामी होटल ग्रुप एक इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर ग्रुप है। राज शेट्टी ने इस होटल को शुरू किया था। इंडिया के साथ-साथ इस ग्रुप के बहरीन, दुबई और ओमान जैसे देशों में भी होटल, रिसॉर्ट और अपार्टमेंट हैं। राज शेट्टी ने 1985 में रामी होटल ग्रुप शुरू किया था। वह अभी इस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में दुबई जाने के बाद 1985 में यह ग्रुप शुरू किया था। रामी ग्रुप के भारत और खाड़ी देशों में 52 होटल हैं।

लंदन यात्रा की अनुमति के लिए शिल्पा-राज की हाईकोर्ट में याचिका

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने लंदन जाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका में दावा किया गया है कि राज कुंद्रा के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी देखभाल के लिए दंपति का लंदन जाना आवश्यक है। दोनों पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है और मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है, जिसे हटाने का अनुरोध भी उन्होंने याचिका में किया है।

राज कुंद्रा के पिता की बिगड़ती सेहत का हवाला

राज कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 10 नवंबर से कुंद्रा के पिता की तबीयत लगातार खराब है। उन्हें कई मेडिकल समस्याएँ हैं और कैप्सूल एंडोस्कोपी कराने की सलाह दी गई है। वह सांस से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी 20 जनवरी 2026 तक लंदन जाने की अनुमति चाहते हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

पहले भी कोर्ट से मिली थी कड़ी शर्तें

इससे पहले, अक्टूबर 2025 में भी दंपति ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। तब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यदि वे विदेश जाना चाहते हैं, तो 60 करोड़ रुपये पहले जमा करें, तभी अनुमति दी जाएगी। अदालत ने उनके मनोरंजन या निजी कारणों से यात्रा पर भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद शिल्पा और राज ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

महाराष्ट्र राजभवन का नाम अब 'महाराष्ट्र लोक भवन'

मुंबई। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंगलवार को केंद्र सरकार के मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र राजभवन का नाम अब आधिकारिक रूप से 'महाराष्ट्र लोक भवन' कर दिया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि यह निर्णय लोकभवन को अधिक जन-केंद्रित, पारदर्शी और लोककल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक कदम है। उन्होंने यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि 'लोक भवन' के रूप में जाना जाने वाला यह भवन अब केवल राज्यपाल का निवास और कार्यालय तक सीमित न रहकर, राज्य के नागरिकों, समाज के विभिन्न वर्गों, छात्रों, शोधकर्ताओं, किसानों और नागरिक संगठनों के साथ संवाद, सहयोग और सहभागिता का एक जीवंत केंद्र बने। राज्यपाल ने यह भी कहा कि 'लोक भवन' का नामकरण इस उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है कि यह भवन सरकार और राज्य की जनता के बीच सेवा, सहयोग और संवाद का एक मजबूत सेतु बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक भवन संविधानिक दायित्वों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह समाज की आशाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर, जनता से सीधा और सार्थक संबंध बनाए रखेगा, तभी यह अपने वास्तविक अर्थ में 'लोक भवन' कहलाएगा।

तीन दिन में हटाया गया 570 मिलियन टन कचरा

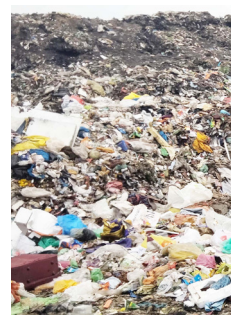

मुंबई । मुंबई नगर निगम (एमएमसी) ने शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 28 से 30 नवंबर तक सड़क सफाई और धूल नियंत्रण अभियान चलाया था। इस अभियान में 570 मीट्रिक टन कचरा, 95 मीट्रिक टन अपशिष्ट और 18 टन सड़क मलबा हटाया गया। इस दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के सफाई कर्मचारियों ने कुल 1,888 किलोमीटर लंबी 676 सड़कों की गहन सफाई की। इस अभियान के साथ-साथ नगर निगम द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में लगातार सुधार होने लगा है। मुंबई मनपा आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

ऑलराउंडर स्टाफ चाहिए:
होटल मधुरम फूड्स ,&
Kitchen कांदिवली वेस्ट मुंबई,
कुक, हेल्पर, डिलीवरी बॉय।
रहना-खाना फ्री।
वेतन योग्यता अनुसार।
add-
Bhumipark Jankalyan Nagar
Malad west
संपर्क:
8433650469 / 7208888007

62 साल की महिला से दुष्कर्म

7 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

62 साल की महिला से रेप और लूट के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने दावा किया था कि वह महिला को वर्षों से जानता था और उसकी सहमति से संबंध बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) को पीड़िता को मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए हैं।

एडिशनल सेशन जज एस. एम. अगरकर ने कहा कि आरोपी की दलील न तो सबूतों के अनुरूप है और न ही परिस्थितियों से मेल खाती है। कोर्ट ने माना कि शिकायत दर्ज कराने में देरी होना सामान्य बात है, क्योंकि समाज में महिलाएं बदनामी के डर से ऐसे अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने में हिचकिचाती हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल की सजा को आवश्यक करार दिया गया।

झूठी कहानी बनाकर महिला को ऑटो में बैठाया

घटना 21 सितंबर 2018 की सुबह की है, जब बोरीवली में काम पर जा रही महिला को आरोपी ने रास्ते में रोककर खुद को उसके बेटे का दोस्त बताया। उसने एक कहानी गढ़ी कि महिला का बेटा होटल में फंसा है क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। इसी बहाने महिला को ऑटो में बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोपी महिला को सुनसान इलाके में ले गया, जहाँ उसने चाकू दिखाकर धमकाते हुए उसके सोने के झुमके और 15,000 रुपए लूट लिए। यह राशि महिला अपनी पोती की स्कूल फीस भरने के लिए ले जा रही थी। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और धमकाकर फरार हो गया। घायल महिला किसी तरह पुलिस चौकी पहुंची और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह 11 दिनों तक रही।

बचाव पक्ष का 'पुराना रिश्ता' वाला दावा खारिज

पुलिस ने पहले लूट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, लेकिन सप्लीमेंट्री बयान के बाद रेप की धाराएं भी जोड़ी गईं। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दावा किया कि 2012 से पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध थे और अफेयर खत्म होने पर महिला ने झूठा केस दर्ज कराया। जज ने इस दावे को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि आरोपी कोई भी संदेह पैदा करने में असफल रहा।

पीड़िता की गवाही को माना विश्वसनीय, मुआवजे का निर्देश

जज ने कहा कि पीड़िता की गवाही भरोसेमंद और ठोस सबूत के रूप में सामने आई। अपराध की क्रूरता, पीड़िता की उम्र और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने DLSA को निर्देश दिया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत पीड़िता को उचित मुआवजा दिया जाए।

गौरी पालवे आत्महत्या मामला

अनंत गरजे की पूर्व प्रेमिका का बयान दर्ज

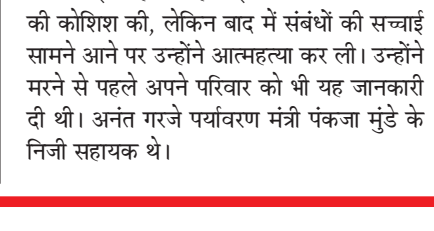

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

डॉ. गौरी पालवे-गरजे आत्महत्या मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। वर्ली पुलिस ने एफआईआर में दर्ज नाम के आधार पर अनंत गरजे की पूर्व प्रेमिका का बयान दर्ज किया है। वहीं, अनंत गरजे की पुलिस हिरासत पूरी होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वर्ली पुलिस की जांच में शामिल की गई पूर्व प्रेमिका ने पूछताछ के दौरान बताया कि 2022 के बाद से उसका अनंत गरजे से कोई संबंध नहीं रहा और वह उनसे संपर्क में भी नहीं थी। उसने यह भी कहा कि गौरी के घर से मिले दस्तावेजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार, उसके बयान में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं जो जांच में मदद कर सकती हैं। जांच में सामने आया है कि गौरी पालवे ने आत्महत्या का कदम तब उठाया, जब उन्हें पति अनंत गरजे के कथित अफेयर के बारे में पता चला। गौरी को कुछ दस्तावेज मिले थे जिन पर अनंत और एक अन्य महिला का नाम लिखा था। ये दस्तावेज गर्भपात से संबंधित थे, जिसे देखकर गौरी सदमे में आ गईं। पहले उन्होंने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाद में संबंधों की सच्चाई सामने आने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मरने से पहले अपने परिवार को भी यह जानकारी दी थी। अनंत गरजे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक थे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ई-निविदा सूचना

विषय: माहुल स्थित एलएमओ प्लांट में एफडीए / पीईएसओ नियमों के अनुसार वेदर शेड की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।

बोली क्रमांक	2025_MCGM_1254105_1
बोली प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 02.12.2025 को सायं 4.00 बजे
बोली समाप्ति दिनांक एवं समय	दिनांक 10.12.2025 को सायं 4.00 बजे
संपर्क अधिकारी का नाम	श्री एन. टी. जाधव
मोबाइल नंबर	9769005647
वेबसाइट	https://portal.mcgm.gov.in/ https://mahatenders.gov.in
ई-मेल पता	aempl.me@mcgm.gov.in

हस्ता/-
पीआरओ /2484 / विज्ञा./2025-26 कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी - दक्षिण)

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई / आरबीओ वर्ली 2025-26/01

निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेतु वाणिज्यिक / कार्यालय परिसर पट्टे पर लेने के संबंध में

भारतीय स्टेट बैंक अपने निम्नांकित शाखाओं के लिए पट्टे (Lease) पर परिसर लेना चाहता है। अपेक्षित परिसर का कारपेट क्षेत्रफल लगभग 2000 से 2500 वर्ग फुट (+/-10%) होना चाहिए। परिसर प्राथमिकता से भूतल (Ground Floor) पर, मुख्य सड़क पर स्थित, अच्छी दृश्यता (Visibility), पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा पार्किंग सुविधा युक्त होना चाहिए। उपयुक्त परिसर के स्वामी इच्छुक पक्ष, नीचे दिए गए पते पर विज्ञापन की तिथि एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर 30 दिनों के भीतर, अर्थात दिनांक 03.01.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं: क्षेत्रीय प्रबंधक (RBOI) क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, जीवन सेवा एनेक्स भवन, एस.वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई - 400054

क्र.	शाखा का नाम	शाखा की स्थिति	मौजूदा	अपेक्षित कारपेट क्षेत्रफल (स्ट्रॉन्ग रूम सहित) 2000-2500 वर्ग फुट (+/-10%)	लॉकर रूम (कारपेट क्षेत्रफल)
1	कालिना शाखा (14914)	वांछित स्थान	कालिना-कुर्ला रोड, कालिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई	2000-2500 वर्ग फुट (+/-10%)	---
2	एसबीआई बांद्रा वेस्ट शाखा (50458)	वांछित स्थान	हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई	2000-2500 वर्ग फुट (+/-10%)	---

केवल वे प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे जो 03.01.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त होंगे। आवेदन "Instructions / Guidelines for submitting the offer" के अनुसार ही किया जाना चाहिए। एस्टेट एजेंट प्रस्ताव के साथ मालिक की प्राधिकरण पत्र (Authorization Letter) संलग्न करें। बैंक द्वारा कोई दलाली (Brokerage) देय नहीं होगी। भारतीय स्टेट बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। प्रपत्र एवं अन्य विवरण SBI की वेबसाइट: sbi.co.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सीलबंद लिफाफे में नीचे दिए गए पते पर कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 03.01.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक जमा किया जाना चाहिए। प्रस्ताव उसी दिनांक 03 जनवरी 2026 को अपराह्न 3.30 बजे खोले जाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी/प्रश्न हेतु कृपया मोबाइल नंबर 8976026123 पर संपर्क करें।
क्षेत्रीय प्रबंधक (RBO-I), State Bank of India, रीजनल बिजनेस ऑफिस, वर्ली, चौथी मंजिल, जीवन सेवा एनेक्स भवन, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, एस. वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई - 400054

संपादकीय

एसआईआर के सवाल

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत-फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा-तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। निस्संदेह, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य-दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। वैसे यदि वास्तव में बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे का समाधान संवेदनशील ढंग से करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाणपत्रों को जुटाने में आ रही परेशानियों के चलते लोग भी बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने प्रदर्शन करके अधिक समय दिए जाने की मांग भी की है। कुछ लोग चुनाव आयोग की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दो-तीन महीने का काम एक माह में पूरा नहीं किया जा सकता।

साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी

कांतिलाल मांडोत
वरिष्ठ पत्रकार,
साहित्यकार-स्तम्भकार

डिजिटल युग की तेज़ी से बदलती दुनिया में भारत जिस रफ्तार से तकनीक को आत्मसात कर रहा है, उसी गति से अपराधियों ने भी अपने मंसूबों को नया रूप दे दिया है। इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और मोबाइल आधारित सेवाओं ने जहां जनजीवन को सरल बनाया है, वहीं इसी सुविधा का दुरुपयोग करते हुए साइबर अपराधी अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें आम नागरिक को यह समझ ही नहीं आता कि वह कब जाल में फंस गया। हाल के महीनों में सबसे भयावह रूप में उभरा डिजिटल अरेस्ट स्कैम न केवल लोगों की कमाई को चूस रहा है, बल्कि नागरिकों के भीतर कानून, सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल तंत्र के प्रति भय भी पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार से इस खतरे की जड़ों तक पहुँचने और इसे खत्म करने का हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा तब गंभीर रूप से उभरा जब अक्टूबर में स्वतः संज्ञान लिए गए इस मामले में गतिशील सुनवाई शुरू हुई और सामने आया कि डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में भारतीयों से तीन हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की ठगी हो चुकी है। यह आंकड़ा सिर्फ आर्थिक नुकसान का नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने का भी है जो आम नागरिक देश की साइबर सुरक्षा प्रणाली से रखता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम का तरीका बेहद खतरनाक और मनोवैज्ञानिक दबाव से भरा होता है। इसमें पीड़ित के मोबाइल पर किसी सरकारी अधिकारी, पुलिस,'सीबीआई,ईडी या अदालत के नाम से कॉल आता है। कॉलर द्वारा दावा किया जाता है कि पीड़ित किसी अपराध में शामिल है और उसकी तुरंत डिजिटल गिरफ्तारी की जा रही है। इसके बाद उससे कहा जाता है कि वह अपने मोबाइल का कैमरा चालू रखे, किसी कमरे में बंद हो जाए और किसी से बात न करे। अपराधी इस दौरान पीड़ित पर डर, तनाव और शर्मिंदगी का इतना दबाव बना देते हैं कि वह बिना समझे अपने पैसे उनके खातों में भेज देता है। यह पूरा घटनाक्रम न केवल अपराधियों की मानसिक तकनीकों को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह बुजुर्ग और अकेले रहने वाले नागरिक ऐसे मामलों में आसानी से निशाना बन जाते हैं। 2025 में ही साइबर ठगी की 1.23 लाख शिकायतें दर्ज होना यह संकेत है कि साइबर अपराध अब सीमित दायरे की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय चुनौती का रूप ले चुकी है। इनमें से 17,718 मामले केवल डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े पाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ठगी मामलों में सबसे ज्यादा निशाना 60 वर्ष से ऊपर के नागरिक बने हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 82 प्रतिशत पीड़ित बुजुर्ग वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें से अधिकांश तकनीक के उपयोग में अपेक्षाकृत कम सहज होते हैं और डिजिटल धमकियों या सरकारी नाम के पीछे छिपी धूर्तता को तुरंत समझ नहीं पाते। युवाओं को लेकर चल रहे साइबर जागरूकता अभियानों के बीच यह वर्ग अभी भी सुरक्षा कवच से बुरी तरह वंचित दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ,जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल हैं ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी नियम भारतीय कानून में अस्तित्व ही नहीं रखता। किसी व्यक्ति को केवल डिजिटल माध्यम से, वह भी बिना किसी विधिक प्रक्रिया के, अरेस्ट करना तो दूर, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार भी किसी एजेंसी को नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से अपराधी सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर आम जनता को भयभीत कर रहे हैं, वह स्थिति अत्यंत गंभीर है और केंद्र सरकार को दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय क्षेत्र नियामकों और आईटी कंपनियों की संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अकेला देश नहीं है जो इस तरह के फिशिंग और धोखाधड़ी नेटवर्क का शिकार हो रहा है। म्यांमार, कम्बोडिया और लाओस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मौजूद साइबर ठगी के बड़े गिरोह इस तरह के अपराधों के प्रमुख स्रोत हैं। 2024 में दर्ज मामलों के विश्लेषण से पता चला कि लगभग 46 प्रतिशत डिजिटल ठगी और डिजिटल अरेस्ट स्कैम की कड़ियाँ इन देशों से जुड़ी हुई थीं। ये देश साइबर अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं जहाँ से वे कॉल सेंटर, सोशल इंजीनियरिंग नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट पाइपलाइन के माध्यम से अपने नेटवर्क को संचालित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले अपराध तंत्र को रोकने के लिए इंटरपोल की सहायता भी मांगी है, ताकि सीमापार जुर्म करने वाले गिरोहों को पकड़ा जा सके।

भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि डिजिटल सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए तुरंत और कड़े कदमों की आवश्यकता है। इसी कड़ी में सारथी ऐप को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है, जो मोबाइल नंबर, पहचान और उपयोगकर्ता की सत्यता की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार ने यह भी बताया कि अब तक लगभग 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन की जांच में भारी संख्या में फर्जी सिम कार्ड पकड़े गए हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर साइबर अपराधी अपने ठगी नेटवर्क को चलाने में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम में दूरसंचार कंपनियों की भूमिका को भी चिन्हित किया है और पूछा है कि सक्रिय नंबरों का सत्यापन कैसे मजबूत किया जा सकता है, ताकि अपराधियों को फर्जी पहचान का सहारा न मिले।

इस समस्या के समाधान में केवल सरकारी एजेंसियों की कोशिशें ही काफी नहीं होंगी, बल्कि वित्तीय संस्थानों विशेषकर आरबीआई और बैंकों को भी बेहद सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ठगी का पैसा आमतौर पर कुछ ही मिनटों में कई डिजिटल वॉलेट, एस्क्रो अकाउंट, क्रिप्टो लिंक और विदेशी खातों में भेज दिया जाता है।

जीवन मंत्र

मेरे पति यहां प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं

जितने सहज, महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह थे, उतनी ही सहज उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी हैं। आज जब मानवता अपने सर्वोत्तम समय की ओर बढ़ रही है, ऐसे में इस सहजता और सादगी की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में एक भोज का आयोजन था। उसी भोज में साधारण कपड़ों में एक महिला एक कोने में बैठकर भोजन कर रही थी। तमाम आला अधिकारियों की पत्नियों को उस भव्य कार्यक्रम के बीच इतनी साधारण महिला की उपस्थिति कुछ खटक रही थी। कुछ ने उत्सुकतावश उनके पास जाकर उनका परिचय जानना चाहा। महिला ने सहज भाव से कहा— "मेरे पति यहां काम करते हैं।"

आला अधिकारियों की महिलाओं का शक अब यकीन में बदलने लगा— जरूर किसी छोटे कर्मचारी की पत्नी यहां आकर इस शानदार कार्यक्रम की शोभा बिगाड़ रही है।

एक महिला ने थोड़ा रौब झाड़ते हुए पूछा— "साफ-साफ बताओ,

तुम्हारे पति किस पद पर कार्य करते हैं?"

महिला फिर से उसी सहजता से बोली—

"जी, वे प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं।"

यह सुनते ही उस सरल-सी महिला की थाली में खत्म हो चुकी मिस्सी रोटी लाने के लिए तमाम अधिकारियों की पत्नियों में होड़ मच गई।

किन्तु गुरशरण कौर ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि वे स्वयं अपना खाना ले लेंगी।

जितने सहज पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह थे, उतनी ही सहज उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी हैं। आज जब मानवता अपने सर्वोत्तम समय की ओर बढ़ रही है, ऐसे में इस सहजता और सादगी की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।

शख्सियत

नंदलाल बोस

भारतीय कला के अग्रदूत

नंदलाल बोस भारतीय कला जगत के एक महान चित्रकार और आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के हवेली खड़गपुर में हुआ। कला के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था, लेकिन उनके माता-पिता इस क्षेत्र को करियर के रूप में स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद नंदलाल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

नंदलाल बोस का नाम भारतीय आधुनिक कला के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने चित्रकला को सिर्फ एक कला रूप नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त माध्यम बनाया। उनकी कला में भारतीय परंपरा, लोक जीवन, मिथक, सरलता और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में अबनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। अबनींद्रनाथ टैगोर न केवल उनके गुरु थे, बल्कि उनके कला-सफ़र के प्रेरणास्रोत भी बने। यहीं उन्होंने जाना कि कला में भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे समाहित किया जाए। इसी दृष्टिकोण ने उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रमुख स्तंभों में स्थापित किया। नंदलाल बोस ने पश्चिमी कलाशैली के प्रभाव से कला को मुक्त कर भारतीय कला के पुनर्जागरण को नई दिशा दी। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन ने उनके विचारों और कृतियों पर गहरा प्रभाव डाला। वे मानते थे कि कला केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम है। इसी भावना से उन्होंने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए प्रसिद्ध 'हरिपुरा पोस्टर्स' तैयार किए। इन चित्रों में भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक-कला, किसानों, मजदूरों, बुनकरों और साधारण जनों की जीवनशैली को बड़े ही सहज और जीवंत रूप में दर्शाया गया। इन पोस्टर्स ने भारतीय कला को जनता के बीच लोकप्रिय और सुलभ बनाया।शांति निकेतन में 'कला भवन' के प्रधानाचार्य के रूप में नंदलाल बोस ने शिक्षा को भी उसी भारतीय भावना से जोड़ा। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को सिर्फ चित्रकला नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें यह समझाया कि कला का मूल उद्देश्य अपनी मिट्टी, संस्कृति और समाज से जुड़ना है। उनके निर्देशन में कला भवन भारतीय कला का वैश्विक केंद्र बना और विश्वभर के कलाकारों ने उनकी शैली का प्रभाव महसूस किया। उनकी कृतियों में भारतीय लघुचित्र शैली, लोक कला, प्राकृतिकता और आधुनिक दृष्टिकोण का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नंदलाल बोस ने न केवल भारतीय कला को नई पहचान दी, बल्कि कला के माध्यम से भारतीयता की एक नई परिभाषा भी रची। 16 अप्रैल 1966 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय कला का आधार स्तंभ है।

जीवन ऊर्जा

ओज़ी ऑस्बॉर्न : जन्म 3 दिसंबर 1948

जन्म

सच्ची ताकत कमजोरियों को अपनाने में है

ओज़ी ऑस्बॉर्न, जिन्हें 'प्रिंस ऑफ़ डार्कनेस' कहा जाता है, का जन्म 3 दिसंबर 1948 को इंग्लैंड में हुआ। वे एक प्रसिद्ध गायक, गीतकार और ब्लैक सबथ बैंड के प्रमुख गायक रहे। अपनी अनोखी शैली और आवाज़ से उन्होंने संगीत जगत में नई पहचान बनाई। उनका जीवन प्रेरणा से भरा है।

सफलता उन्हें मिलती है, जो जीवन की कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते। जीवन आपको गिरा सकता है, लेकिन असली ताकत फिर से खड़े होने में है। अपनी कमियों को अपनाएं, क्योंकि वही आपको अद्वितीय बनाती हैं। डर क्षणिक है, लेकिन पछतावा हमेशा के लिए रहता है। जोखिम उठाएं। अपने जुनून को अपना मार्गदर्शक बनाएं, भले ही दुनिया आप पर शक करे। हर चुनौती आपके साहस को साबित करने का अवसर है। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा सार्थक होता है। दुनिया की शोरगुल को अपने भीतर की आवाज को दबाने न दें। गर्व से अलग दिखें, क्योंकि दुनिया में वैसे लोग बहुत हैं जो केवल फिट होने की कोशिश करते हैं। रचनात्मकता साधारण के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह है। दृढ़ता सपनों को वास्तविकता में बदल देती है, एक-एक कदम से। अंधकार इसलिए होता है ताकि आप अपनी रोशनी खोज सकें। सफलता का मतलब पूर्णता नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना है। जीवन आपका मंच है—पूरे दिल से प्रदर्शन करें। आपके निशान उन लड़ाइयों के प्रतीक हैं, जिन्हें आपने जीत लिया है। कभी सीखना बंद न करें, क्योंकि विकास ही जीवन का सार है। प्रामाणिकता हमेशा नकलीपन से आगे निकलती है। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, क्योंकि वह रास्ता जानता है। गलतियां यह साबित करती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं—उन्हें कभी न डरें। अराजकता को गले लगाएं, क्योंकि यह अक्सर सबसे सुंदर क्षणों की ओर ले जाती है। मंजिल से ज्यादा यात्रा मायने रखती है—इस सफर का आनंद लें। सच्ची ताकत कमजोरियों को अपनाने में है। अपनी कहानी को ऐसा बनाएं कि वह दूसरों को अपनी कहानी लिखने की प्रेरणा दे।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्य प्रदेश

माथे पर तिलक लगाने का महत्व

तिलक लगाने की परंपरा और तिलक क्यों लगाया जाता है इससे क्या लाभ होता है। सनातन परंपरा में माथे पर तिलक लगाने का काफी महत्व माना गया है। विवाहित स्त्रियां माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती हैं. पूजा के समय या किसी भी शुभ कार्य के मौके पर भी मस्तक पर तिलक जरूर लगाया जाता है। अलग अलग मौकों पर अलग चीजों से तिलक लगाने का चलन है। ये संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है-ः धार्मिक मान्यता के अनुसार मस्तक के बीचोंबीच भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा त्रिदेव का निवास होता है. उस स्थान पर ही तिलक भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। महिलाएं इसे देवी का आशीर्वाद मानकर मस्तक पर लगाती हैं। इसके अलावा इस स्थान को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर शरीर की तीन नाड़ियां एक साथ मिलती हैं। यही स्थान मन व गुरु का भी होता है, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस स्थान पर तिलक लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का तेज बढ़ता है। हमारी संस्कृति में प्रातः काल स्नान के बाद तिलक लगाने की परंपरा वैदिक काल से है। और तिलक लगाने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर में सात चक्र होते हैं, इन्हें ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. मस्तक के बीचोंबीच आज्ञाचक्र होता है. यही स्थान पीनियल ग्रन्थिका होता है. जब उस स्थान पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रन्थि का उद्दीपन होता है इससे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल अवयन जागृत होते हैं। मस्तक पर तिलक लगाने से बीटाएंडोरफिन और सेराटोनिन नामक रसायनों का स्राव भी संतुलित होता है। इससे मस्तिष्क शांत होता है। एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। कुछ वर्षों तक लगातार तिलक लगाने से आपकी मूल्यांकन क्षमता और दूरदर्शिता में अद्भुत विकास होता है। प्रतिदिन तिलक लगाने से धीरे-धीरे आपके अंदर सिक्स्थ सेंस का जागरण होता है जिसकी वजह से आप भविष्य में आने वाली आपात घटनाओं व समस्याओं का आभास आपको होने लगता है,और आप कॉफी समस्याओं व दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सबसे उत्तम तिलक केसर, हल्दी, कुमकुम, रोली, सिन्दूर और चंदन के होते हैं, इनमें से कोई भी तिलक लगाएंगे वो आपको निश्चित लाभ देगा। ध्यान रहे कृत्रिम वस्तुओं का तिलक कोई लाभ नहीं देता। अतःतिलक हमेशा शुद्ध व प्राकृतिक वस्तुओं का ही लगायें जैसेचंदन, हल्दी, केसर इत्यादि। तिलक को आप गंगाजल से या गुलाब जल से गिला कर सकते हैं। तिलक लगाने का लाभ तभी मिलेगा जब नियमित रूप से तिलक लगाया जाए और कम से कम दोपहर तक तिलक माथे पर रहना आवश्यक है। निश्चित मानिए जब आप अपने प्रभु के नाम का प्रतिदिन प्राकृतिक वस्तुओं का तिलक लगाना शुरू करेंगे तो आपके विचार भी सुंदर होंगे और आपका चेहरा भी आकर्षक लगेगा।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

अगर किसी का कानूनी दर्जा ही नहीं है और वह घुसपैठिया है, तो क्या हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे यहां रखें? अगर उनके पास भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है और वे घुसपैठिए हैं, तो क्या हम उत्तर भारत की बेहद संवेदनशील सीमा पर आए किसी घुसपैठिए का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करें?

-जस्टिस सूर्यकांत, CJI और बेंच

मैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कहना चाहूंगा कि मैंने स्वयं आज स्थगित प्रस्ताव दिया हुआ है करा ले वो चर्चा। उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो देश के सामने सच आए। मैं सदन में 646 पेज दिखाकर पूछा कि ये नाम कहां से गायब हो गए किसने नाम हटाया?

-राजीव राय, सपा सांसद

'एसआईआर के नाम पर पूरे देश में धांधली चल रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए खुल के वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन कर रहा है।

- सौरभ भारद्वाज, नेता,आप पार्टी

आरजेडी के विधायक भी अपने नेता से खुश नहीं हैं। कब तक खुश रहते हैं यह बात कोई नहीं जानता। ऐसे में तेजस्वी यादव कब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बचा पाते हैं यह बात खुदा ही जानता है। अगर दो सीट कम मिलते तो इसमें भी मुश्किल था। इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर काम करना चाहिए।

-शाहनवाज हुसैन, नेता, भाजपा

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

वारिसों को ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कैटेगरी के पदों पर सरकारी और गैर-सरकारी नौकरी

ठाणे। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हत्या या एट्रोसिटी से हुई मौत के मामलों में मृतक के योग्य वारिसों को ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों पर नौकरी देने के लिए सरकार ने विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमेटी की सिफारिश के आधार पर सामाजिक कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे को दोनों—सोशल वेलफेयर व ट्राइबल डेवलपमेंट—विभागों में रिक्त पदों का समन्वय कर नियुक्ति मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। निर्देशों के अनुसार, एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज हत्या के मामलों में योग्य वारिसों को सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नौकरी देने की लंबित कार्रवाई संबंधित जिला प्रशासन और ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग के समन्वय से 26 जनवरी 2026 तक पूरी करनी होगी। इसके लिए ठाणे जिले के पीड़ित परिवारों को 15 दिसंबर 2025 से पहले अपने दस्तावेज असिस्टेंट कमिश्नर, सोशल वेलफेयर कार्यालय, 4th फ्लोर, सामाजिक न्याय भवन, कलवा, ठाणे-400605 में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोलापुर-अनकापल्ले साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें 8 अतिरिक्त फेरों के लिए जारी रखेगा रेलवे

सोलापुर। रेलवे सोलापुर और अनकापल्ले के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों की सेवाएँ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 8 अतिरिक्त फेरों के लिए जारी रखेगा। ट्रेन संख्या 01477 सोलापुर-अनकापल्ले साप्ताहिक स्पेशल, जिसे 28.11.2025 तक चलाने के लिए अधिसूचित किया गया था, अब 05.12.2025 से 26.12.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को जारी रहेगी। ट्रेन संख्या 01478 अनकापल्ले-सोलापुर साप्ताहिक स्पेशल, जिसे 29.11.2025 तक चलाने के लिए अधिसूचित किया गया था, अब 06.12.2025 से 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को जारी रहेगी।

दौंड-कलबुर्गी के बीच विशेष रेल सेवाओं का संचालन रहेगा जारी

सोलापुर। मध्य रेलवे ने यात्रियों की मांग पर सोलापुर मंडल होकर दौंड-कलबुर्गी के बीच चलने वाली विशेष रेल सेवाओं की अवधि बढ़ा दी है। अब ट्रेन संख्या 01421/01422 दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित स्पेशल, जिन्हें पहले 1 दिसंबर 2025 तक सप्ताह में 5 दिन (गुरुवार और रविवार छोड़कर) चलाने की मंजूरी थी, 28 फरवरी 2026 तक संचालित होंगी, जबकि ट्रेन संख्या 01425/01426 दौंड-कलबुर्गी द्वि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल, जो पूर्व में 30 नवंबर 2025 तक गुरुवार और रविवार को चलनी थी, अब 26 फरवरी 2026 तक चलेगी। सभी ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना पूर्ववत रहेंगे।

इंदौर – मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस का शॉर्ट टर्मिनेशन

मुंबई। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल कार्य कार्य के लिए 60 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी कारण ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस बुधवार और शुक्रवार को दादर स्टेशन पर तथा रविवार को बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। यह व्यवस्था आगे के आदेश तक जारी रहेगी।

स्कूलों की भागीदारी के साथ ठाणे पुलिस का रोड सेफ्टी अभियान

ठाणे। ठाणे यातायात पुलिस विभाग ने बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी रोड सेफ्टी कैंपेन 2026 में एक नई पहल की है। 26 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान में ठाणे के स्कूलों को शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा RSP के विभिन्न विभागों के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। इनमें प्रथम तीन विजेता छात्रों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

मध्य रेल के 11 कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार

सीएसएमटी में सम्मान समारोह का आयोजन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मध्य रेल के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने 2 दिसंबर 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मुंबई में आयोजित समारोह में 11 कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए। इनमें मुंबई मंडल के 3, पुणे मंडल के 4, नागपुर मंडल के 2, सोलापुर मंडल के 1 और भुसावल मंडल के 1 कर्मचारी शामिल रहे।

सतर्कता और समय रहते कार्रवाई के लिए पुरस्कार

ये पुरस्कार उन कर्मचारियों को दिए गए जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान सतर्कता दिखाते हुए संभावित दुर्घटनाओं को टाला। पुरस्कार में पदक, प्रशंसा प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और 3500 का नकद पुरस्कार शामिल रहा।

नागपुर मंडल के कर्मचारियों ने रोका बड़ा खतरा

नागपुर मंडल के ट्रेन मैनेजर रवि वर्मा ने मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआँ उठता देख तुरंत कार्रवाई की, जिससे हॉट एक्सल के कारण होने वाली दुर्घटना टल गई। वहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर राजेश राउत ने रेल फ्रैक्चर पहचानकर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को सुरक्षित दिशा में मोड़ा।

मुंबई और पुणे मंडल के कर्मचारियों की सराहनीय कार्रवाई

मुंबई मंडल के ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर और हेल्पर ने समय रहते पुर्जे के लटकने, रेल फ्रैक्चर और अन्य खतरनाक स्थितियों को पहचानकर बड़े हादसे को टाल दिया। वहीं पुणे मंडल में लोको पायलट डी.के. यादव, पुलिस उप-निरीक्षक नरेंद्र कुंभार और तकनीशियन चेतन भालवनकर सहित चार कर्मचारियों की सतर्कता से कई संभावित दुर्घटनाएँ रोकी गईं और एक यात्री की जान तक बचाई गई।

सोलापुर और भुसावल मंडल की सतर्क टीम

सोलापुर के अनगर स्टेशन मास्टर विक्रम मीणा ने मालगाड़ी में हॉट एक्सल देखकर ट्रेन रोक सवारों और रेल संपत्ति को सुरक्षित किया। भुसावल मंडल के लोको पायलट एल.जे. चौधरी ने टूटकर लटक रही हैंड असेंबली की समय पर पहचान कर एक बड़े हादसे को टाल दिया। महाप्रबंधक ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सतर्कता और समर्पण अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक प्रतीक गोस्वामी, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी चंद्र किशोर प्रसाद सहित मध्य रेल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हम विकास के साथ कुंभ मेले की पवित्रता को भी बनाए रखेंगे: मुख्यमंत्री

दीपक पवार । मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दक्षिणी गंगा गोदावरी की सफाई और संरक्षण के लिए नागरिकों व निवेशकों की स्वैच्छिक भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' संदेश के अनुरूप ही नासिक कुंभ मेले की पवित्रता और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए सभी विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नासिक महानगरपालिका के 'क्लीन गोदावरी बॉन्ड' की सूचीबद्धता के अवसर पर उन्होंने यह बात कही।

गोदावरी संरक्षण पर विशेष फोकस

कार्यक्रम में एनएसई के एमडी आशीष चौहान, 'मित्र' के सीईओ प्रवीण परदेशी, डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेडाम, कुंभ मेला कमिश्नर शेखर सिंह और नगर आयुक्त मनीषा खत्री मौजूद रहे। फडणवीस ने बताया कि नासिक क्षेत्र में कुंभ मेले के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी की सफाई, विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन रखते हुए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की इनोवेटिव फाइनेंशियल सोच से और गति मिली है।

ऊर्जा कंपनियों की भी एनएसई में लिस्टिंग की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'क्लीन गोदावरी बॉन्ड' को निवेशकों से चार गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला, जो नासिक महानगरपालिका की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स भी नियामकीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसी तरह ओपन मार्केट से फंड जुटा सकती हैं, जिससे विकास कार्यों को बड़ी मदद मिलेगी। फडणवीस ने यह भी बताया कि एनएसई प्रक्रिया के तहत 26 करोड़ रुपये का इंसेंटिव फंड मिलेगा, जिससे ब्याज का बोझ लगभग शून्य पर आ जाएगा। साथ ही, पहली बार महापारेषण, महावितरण और महानिर्मिति जैसी ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को एनएसई में लिस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी उपलब्ध होगी।

2 लाख 84 हज़ार गाड़ी मालिकों ने एचएसआरपी के लिए किया ऑनलाइन अप्लाई

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य किए जाने के बाद ठाणे ज़िले में वाहन मालिकों की ओर से तेज़ी से आवेदन किए जा रहे हैं। ठाणे RTO की वेबसाइट पर अब तक 2 लाख 84 हज़ार लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। नकली नंबर प्लेट, चोरी की गाड़ियां और गलत पहचान जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को सभी पुराने वाहनों पर HSRP लगवाना ज़रूरी कर दिया। 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन मालिकों को यह प्लेट लगवानी अनिवार्य है।

अब तक लाखों वाहन अपडेटेड

ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल के मार्गदर्शन में यह कैंपेन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 2 लाख 75 हज़ार वाहन मालिकों को अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 06 हज़ार लोगों ने अपनी गाड़ियों पर नई HSRP लगवा भी ली है। उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर के अनुसार विभाग ने प्लेट लगाने के लिए तीन अधिकृत कंपनियों को नियुक्त किया है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति वाले वेंडरों से लगाई गई प्लेटें सरकारी डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं होतीं, जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है।

31 दिसंबर 2025 के बाद बिना HSRP पर कार्रवाई होगी

परिवहन विभाग के अनुसार 31 दिसंबर 2025 के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर पेनल्टी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे www.transport.maharashtra.gov.in पर जाकर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें, वाहन की डिटेल भरें और अपॉइंटमेंट लेकर प्लेट लगवाएं। मीरा-भयंदर में भी HSRP को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां 37 हज़ार आवेदन मिले हैं और 27,156 वाहनों पर नई प्लेट लग चुकी है।

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण ने किया बस सेवा का निरीक्षण

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

शहर की बदहाल परिवहन सेवा को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों का जायजा लेने के लिए उल्हासनगर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण ने मंगलवार को स्वयं बस में सफर कर स्थितियों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्हें कई खामियां मिलीं। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस परिवहन सेवा में इका नामक पुणे की कंपनी को सौ बसें चलाने का ठेका दिया गया था, जिनमें से फिलहाल 20 सामान्य और 20 वातानुकूलित बसें बदलेपुर-कल्याण, टिटवाला मंदिर, शिवमंदिर आदि मार्गों पर संचालित हो रही हैं। 1 दिसंबर 2025 को किए गए निरीक्षण में अतिरिक्त आयुक्त ने पाया कि बसें समय पर नहीं चल रहीं, उनमें गंदगी और साफ-सफाई की कमी है, स्वचालित डिस्प्ले बोर्ड बंद पड़े हैं और अग्निशमन यंत्र निर्धारित स्थान पर नहीं है। तमाम खामियों पर उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए और बस ठेकेदार पर लापरवाही के लिए कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

घोडबंदर रोड परिसर में खतरनाक हुई हवा

वातावरण प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाएं: पूर्व डिप्टी मेयर

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

कापरबावड़ी से गायमुख तक घोड़बंदर रोड क्षेत्र में मेट्रो कार्य, सर्विस रोड निर्माण, पानी की पाइपलाइन बिछाने और इमारतों के निर्माण के चलते बड़े पैमाने पर सड़कें खोदी गई हैं। इनसे उठ रही मिट्टी और धूल के कारण गंभीर वायु प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। इसी के चलते पूर्व डिप्टी मेयर नरेश मनेरा ने ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हवा की बेहद खराब गुणवत्ता नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गई है और तत्काल नियंत्रण उपाय जरूरी हैं।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग की लापरवाही पर गंभीर आरोप

मनेरा ने आरोप लगाया कि मनपा का प्रदूषण नियंत्रण विभाग नियमों का पालन नहीं करा रहा है, जबकि सड़क खोदाई वाले स्थानों पर पानी छिड़काव, डंपरों को ढककर मिट्टी ले जाना और निर्माण स्थलों पर कवर लगाने जैसे नियम पहले से तय हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद विभाग की 'सुस्ती' के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने अपने पत्र में तंज करते हुए पूछा कि यह प्रदूषण नियंत्रण विभाग है या प्रदूषण बढ़ाने वाला विभाग, क्योंकि इसकी लापरवाही से घोड़बंदर रोड के नागरिक सांस और आंखों की समस्याओं से परेशान हैं।

महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पश्चिम रेलवे ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस (6 दिसंबर 2025) पर दादर स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों के लिए व्यापक सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन की तैयारी की है। लगभग 700 जीआरपी और आरपीएफ जवान प्लेटफॉर्म, पुलों, प्रवेश-निकास द्वारों सहित पूरे स्टेशन परिसर में तैनात रहेंगे। 160 सीसीटीवी कैमरों और अत्याधुनिक वीडियो एनालिटिक्स जैसे फेस रिकग्निशन, पीपल डेंसिटी एनालिसिस और लेफ्ट-ओवर बैगेज डिटेक्शन के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी।

हेल्प डेस्क और एंटी-सैबोटाज जांच की व्यवस्था

पश्चिम रेलवे के अनुसार दादर स्टेशन पर आगंतुकों और चैत्यभूमि की ओर जाने वाले अनुयायियों की सहायता हेतु कई 24x7 हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन पर मौजूद आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच कर्मचारी आगंतुकों को चैत्यभूमि, राजगृह, ट्रेन समय तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सुरक्षा के लिए आरपीएफ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जीआरपी BDDS टीम आधुनिक उपकरणों की मदद से लगातार एंटी-सैबोटाज जांच करेंगी। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बीएमसी व तिलक एफओबी जैसी भीड़-प्रवण जगहों पर बैरिकेडिंग व सेगरेगेशन की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए सभी पुलों और द्वारों पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाए गए हैं। दादर स्टेशन पर डॉक्टर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सहित 24x7 चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। परिसर में प्रकाश व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं। पश्चिम रेलवे ने सभी अनुयायियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि वह महापरिनिर्वाण दिवस पर आगंतुकों को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

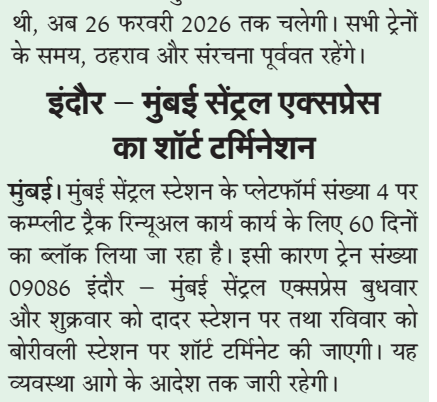

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष धनार्जन होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। व्यापार-व्यवसाय में इच्छित लाभ की संभावना है। भाइयों की मदद मिलेगी। संपत्ति के लेनदेन में सावधानी रखें।

वृष संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रचार-प्रसार से दूर रहें। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा।

मिथुन जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान प्राप्त हो सकेगा। व्यापारिक निर्णय लेने में देर नहीं करें। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी।

कर्क भौतिक विकास के कार्यों को बल मिलेगा। फालतू खर्च होगा। भागीदारी के प्रस्ताव आएंगे। दिनचर्या नियमित रहेगी। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम न लें। झंझटों में न पड़ें। आय में कमी होगी।

सिंह प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। बुद्धि एवं मनोबल से सुख-संपन्नता बढ़ेगी। व्यापार में कार्य का विस्तार होगा। सगे-संबंधी मिलेंगे।

कन्या मान बढ़ेगा। मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। अभिष्ट कार्य की सिद्धि के योग हैं। उलझनों से मुक्ति मिलेगी।

तुला स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दु:खद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वास्तविकता को महत्व दें। प्रयासों में सफलता के योग कम हैं। परिवार में कलह-कलेश का माहौल रह सकता है।

वृश्चिक यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी। प्रयास की मात्रा के अनुसार लाभ की अधिकता रहेगी।

धनु उदर विकार के योग के कारण खान-पान पर संयम रखें। विवादों से दूर रहना चाहिए। आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें।

मकर धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेतृत्व गुण की प्रधानता के कारण प्रशासन व नेतृत्व संबंधी कार्य सफल होंगे। शत्रुओं से सावधान रहें। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे।

कुंभ समय की अनुकूलता का लाभ अधिकाधिक लेना चाहिए। नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति संभव है। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है।

मीन रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवहार कुशलता एवं सहनशीलता के बल पर आने वाली बाधाओं का समाधान हो सकेगा। खानपान पर नियंत्रण रखें। नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी।

शंख: वह अनसुना नाद जो भाग्य को जगाता है

प्रियंका जैन
9769994439

इस प्रश्न का उत्तर केवल "हाँ" या "नहीं" में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शंख केवल एक वस्तु नहीं है—वह हजारों वर्षों की आध्यात्मिक खोज, वेदों की ध्वनि, समुद्र मंथन का देव-रत्न, और नाद-ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। शंख को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि सिर्फ कंपन नहीं—ध्वनि ही ऊर्जा है, ध्वनि ही प्राण है, ध्वनि ही शक्ति है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो पहले प्रकाश नहीं—नाद हुआ। बाद में वही नाद ॐ बना, वही सृष्टि-चेतना बना, वही प्राण-अंकुर बनकर चारों दिशाओं में फैल गया। शंख की ध्वनि उसी मूल नाद की अनुगूँज है, जो लाखों वर्षों से देवताओं का प्रिय साधन बनी रही।

पुराणों में यह अत्यंत स्पष्ट है कि युद्ध में शंखनाद करना केवल एक संकेत-ध्वनि नहीं था—वह मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सूक्ष्म-ऊर्जा-स्तर पर काम करने वाली एक उच्च ध्वनि-क्रिया थी। जब श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य बजाया तो वह केवल ध्वनि नहीं थी; वह एक आकाशीय कंपन था जिसने शत्रुओं का मनोबल तोड़ा और मित्रों का उत्साह बढ़ाया। अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौण्ड्र, युधिष्ठिर का अनंतविजय—ये सब शंख केवल खोल नहीं थे, हर एक में प्राण प्रतिष्ठित थे।

पुराण कहते हैं कि शंख की ध्वनि भूत-प्रेत, राक्षस, काली शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है। यह घटना कोई चमत्कार नहीं—यह विज्ञान है। ध्वनि-कंपन जहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक सूक्ष्म जीवाणुओं और नकारात्मक आवृत्तियों का विनाश होता है। शंख का कंपन सामान्य कंपन नहीं है—वह सर्पिल ऊर्जा है, जो दाएँ-बाएँ घूमते हुए वातावरण को शुद्ध करती है। यह वही कारण है कि भारतीय घरों में संध्या-काल में शंख बजाना शुभ माना गया। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के समय तमोगुण बढ़ते हैं, और शंखनाद उस तमोगुण को नष्ट कर देता है।

लेकिन शंख की कहानी केवल यहाँ तक सीमित नहीं।

शंख समुद्र मंथन के समय जब निकला था, तो देवताओं ने उसे दिव्य-रत्न माना। लक्ष्मी साथ उत्पन्न हुईं, इसलिए शंख को लक्ष्मी का भ्राता कहा गया। जहाँ शंख होता है—वहाँ समृद्धि का निवास होता है, यह कोई आस्था नहीं—यह अनुभव है, परंपरा है, और अनेक परिवारों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। शंख देवताओं का प्रतीक है, पर एक महत्वपूर्ण अपवाद है—शिव। शिव को शंख से जल नहीं अर्पित किया जाता, क्योंकि शंखचूड़ दैत्य, जिसका वध स्वयं शिव ने किया, वही शंख जाति का पूर्वज माना जाता है। इसलिए शंख का जल शिव पर वर्जित है, पर अन्य सभी देवताओं पर यह परम पवित्र है।

(क्रमशः)

न्यूज़ ब्रीफ

सेना को मिले 565 अग्निवीर, कमांडेंट ने दिलाई शपथ

फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 31 सप्ताह की कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को 565 रिक्रूट को सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल किया गया। राजपूत रेजिमेंट के ऐतिहासिक करिअप्पा मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में ब्रिगडियर माइकल डिसूजा ने परेड का निरीक्षण किया, जबकि अग्निवीर रिक्रूट दुष्यंत प्रताप सिंह ने परेड कमांडर के रूप में नेतृत्व किया। अग्निवीरों के कदमों की गूँज रेजिमेंट परिसर में सुनाई दी और माता-पिता व परिजन भी अपने बच्चों को सैनिक वर्दी में देखकर उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ने सभी अग्निवीरों और रिक्रूट्स को बधाई देते हुए कहा कि यह गौरव और जिम्मेदारी का समय है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में प्राप्त कर्तव्य, निष्ठा और बलिदान के मूल्यों को अब राष्ट्र सेवा में उतारने का समय आ गया है। कुल 427 अग्निवीर और 138 प्रादेशिक सेना रिक्रूट इस बैच में शामिल हुए, जिसमें यश चौहान को 'बेस्ट इन मेरिट' के लिए सम्मानित किया गया। कमांडेंट ने अग्निवीरों को युद्ध और सुरक्षा के बदलते तरीकों से निपटने के लिए नई तकनीक सीखते रहने की भी सलाह दी।

बिहार विधानसभा : डॉ. प्रेम कुमार बनेंगे निर्विरोध 18वें स्पीकर

पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन डॉ. प्रेम कुमार का स्पीकर के रूप में चुनाव होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गया से नौ बार विधायक रहे डॉ. कुमार अकेले उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। डॉ. कुमार पहली बार 1990 में विधायक बने थे और अब तक लगातार जीतते हुए बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान बना चुके हैं। वे 2015 से 2017 तक नेता प्रतिपक्ष रहे और विभिन्न मंत्रित्वकालों में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। सत्र की कुल पांच बैठकें होंगी और यह 18वीं विधानसभा की पहली बैठक है। विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में अपनी रणनीति के साथ उतरेंगे। डॉ. कुमार भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा और नंदकिशोर यादव के बाद तीसरे स्पीकर होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता के रूप में उनका अनुभव और राजनीतिक पकड़ सदन में नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करेगी।

बिजली विभाग के दो कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में मीरजापुर की एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को बिजली विभाग के दो कर्मचारियों को बिजली बिल कम कराने के नाम पर तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन मीरजापुर के प्रभारी अनिल कुमार चौरसिया ने बताया की दुद्धी कस्बा स्थित एक श्रृंगार स्टोर के संचालक अनिल कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी की बिजली विभाग के दो कर्मचारी बिजली का बिल अधिक बना दिया और उसे कम करने के लिए अब घूस मांग रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने इस मामले में अपना जाल बिछाया। कर्मचारी जब रिश्वत लेने के लिए श्रृंगार स्टोर पर पहुंचे और हाथ में जैसे ही रुपये लिए टीम ने उन्हें दबोच लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्टः वकीलों के आपराधिक मामलों का ब्यौरा तलब

एजेंसी । प्रयागराज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और डीजीपी अभियोजन को आदेश दिया कि वे राज्य भर में वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। अदालत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब कुछ वकील बार एसोसिएशनों में प्रमुख पदों पर हैं और उनका आपराधिक इतिहास कानून के शासन के लिए संभावित खतरा बन सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपने परिवाद को खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई में अदालत को यह जानकारी मिली कि याची स्वयं कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है, और उसके भाई कुख्यात अपराधी हैं। न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर तथ्य है कि याची तीन आपराधिक मामलों में आरोपित है और उसके सभी भाई गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं। अदालत ने वकीलों की आपराधिक पृष्ठभूमि के न्याय प्रशासन पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की।

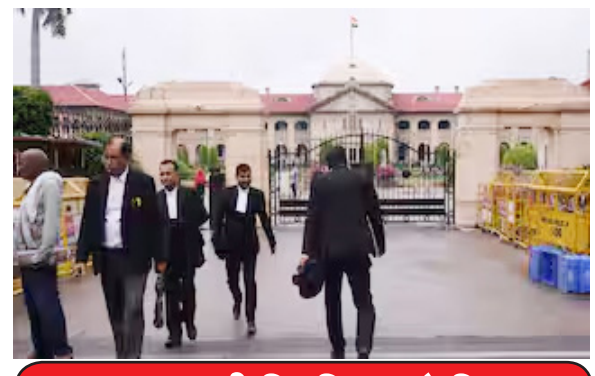

ट्रायल तक की स्थिति का हो विवरण

अदालत ने निर्देश दिया कि सभी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी और संयुक्त निदेशक अभियोजन यूपी बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। इसमें एफआईआर पंजीकरण की तिथि और अपराध संख्या, लागू धाराएं और संबंधित थाना, विवेचना की वर्तमान स्थिति, चार्जशीट दाखिल करने और आरोप तय करने की तिथि, परीक्षित गवाहों का विवरण और ट्रायल की वर्तमान स्थिति का विवरण होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस संबंधी विवरण डीजीपी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि अभियोजन पक्ष की जानकारी डीजीपी अभियोजन द्वारा दी जाएगी। अदालत ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा ।याचिका में मोहम्मद कफील ने इटावा के अपर सत्र न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को तलब करने की उनकी प्रार्थना खारिज कर दी गई थी।

याची ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

याची ने अपने पूरक हलफनामे में स्वीकार किया कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, हालांकि उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उसे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया। दूसरी ओर, इटावा कोतवाली के इंस्पेक्टर द्वारा दाखिल हलफनामे में यह तथ्य सामने आया कि याची, जो पेशे से अधिवक्ता है, कुल तीन आपराधिक मामलों में अभियुक्त के रूप में शामिल है। यह खुलासा अदालत की उस चिंता को मजबूत करता है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेशेवरों का चरित्र और आचरण पारदर्शी होना चाहिए। अदालत का यह आदेश वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड पर स्पष्टता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अयोध्याः अब 52 एकड़ में बनेगा विश्वस्तरीय 'मंदिर संग्रहालय'

योगी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

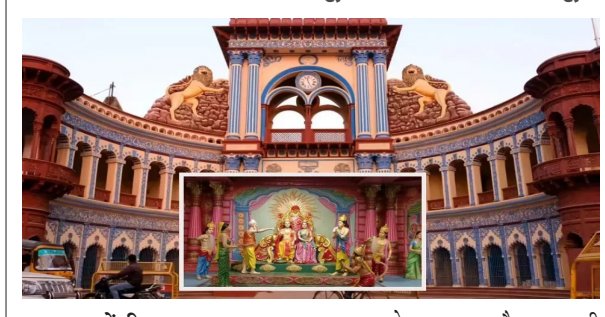

एजेंसी । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने टाटा सन्स के सहयोग से प्रस्तावित 'मंदिर संग्रहालय' के लिए पहले तय 25 एकड़ की जगह अब कुल 52.102 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह कदम अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक–आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि टाटा सन्स अपने सीएसआर फंड से इस विश्वस्तरीय संग्रहालय का निर्माण और संचालन करेगी। यह परियोजना कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी एसपीवी के माध्यम से संचालित होगी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टाटा सन्स के बीच गत 3 सितंबर को त्रिपक्षीय एमओयू हो चुका है। टाटा सन्स ने संग्रहालय को और भव्य स्वरूप देने की योजना के तहत अतिरिक्त भूमि की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने मांझा जमथरा गांव स्थित कुल 52.102 एकड़ नजूल भूमि को पर्यटन विभाग के माध्यम से परियोजना के लिए स्वीकृत कर दिया है। कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब ऐसे खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों तथा यात्रा की अवधि को सेवा अवधि यानी 'ड्यूटी' के रूप में गिना जाएगा।

4,300 छातों में पैक की थी 1042 करोड़ की ई-सिगरेट

एजेंसी । नई दिल्ली

राजस्व खुफिया निदेशालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर ई-सिगरेट की अवैध तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की खेप जब्त कर ली है। विभाग ने इस ऑपरेशन में 10.42 करोड़ रुपये मूल्य की 45,984 ई-सिगरेट बरामद की हैं और तीन तस्करों को हिरासत में लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, डीआरआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि चीन से भेजे गए एक कंटेनर में छातों के सामान की आड़ में प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बड़ी मात्रा भारत में उतारी जानी है। उसी आधार पर 27 नवंबर को कंटेनर की जांच की गई।

कस्टम्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

जांच के दौरान शुरुआती कार्टन में सामान्य छाते पाए गए, लेकिन गहराई से जांच करने पर इनके पीछे बड़ी मात्रा में विभिन्न फ्लेवर वाली ई-सिगरेटें छिपी हुई मिलीं। कुल 45,984 ई-सिगरेट बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 .41 करोड़ रुपये बताई गई है। इन्हें 4,300 छातों (कीमत लगभग 4 .30 लाख रुपये) के साथ बारीकी से पैक कर तस्करी का प्रयास किया गया था। डीआरआई ने इस पूरे माल को कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत जब्त कर लिया है।

हादसे का शिकार हुई नेपाली तीर्थयात्रियों की बस, दो की मौत

एजेंसी । काठमांडू/बलरामपुर

नेपाल से तीर्थयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भीषण हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में दो नेपाली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 24 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार देर रात करीब 2 बजे हुई। जानकारी के अनुसार यूपी-22 एटी-0245 नंबर की यह बस बुटवल स्थित शुभसाइत ट्रैवल्स की थी, जिसमें कुल 45 यात्री सवार थे। सभी यात्री बुटवल और उसके आसपास रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस रास्ते में एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद वाहन में अचानक आग भड़क उठी। इसी कारण कई यात्री जलने से घायल हुए और दो की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रूपन्देही जिला पुलिस कार्यालय ने बताया कि नेपाल पुलिस को इस हादसे की आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है। जिला पुलिस के सूचना अधिकारी डीएसपी सूरज कार्की ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के जरिए घटना की जानकारी हुई है और इस संबंध में बलरामपुर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। हादसे में मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति को लेकर भारतीय प्रशासन जल्द विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।

बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने दान की आंखें

एजेंसी । बागपत

उत्तर प्रदेश के बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने एक प्रेरणादायी कार्य करके बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने नेत्र अस्पताल के एक कार्यक्रम में अपनी आंखों का दान कर सबको चकित कर दिया। उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर लोगों को मानवता का बड़ा संदेश दिया है। वे बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे में रविवार को एडीके जैन नेत्र अस्पताल के 6वें फाउंडेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और नेत्र स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं को करीब से देखा। इस बीच आयोजकों की ओर से जिलाधिकारी से भी मंच से जागरूकता के लिए अपील करने की प्रार्थना की गई। आयोजक संस्था जिले में नेत्र शिविर आयोजित करती है। इसके बाद उन्होंने मंच से कार्यक्रम में आये लोगों से भी नेत्र दान की अपील की।

मीडिया से दूर रखा अपना निर्णय

जिलाधिकारी के इस निर्णय से आयोजक नगीन गुप्ता भी प्रभावित हुए बिना नहीं सके। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने मंच से एक बड़ा संदेश दिया है कि किसी को मानवता के लिए प्रेरित करने से पहले खुद उन कदमों पर चलना होगा। उनके इस कार्य को देखकर ईश पुत्र संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। नगीन गुप्ता का कहना है कि बागपत की यह पहली जिलाधिकारी हैं जिन्होंने मानवता के लिए एक मिसाल कायम की है, लेकिन अपने इस निर्णय को मीडिया से दूर रखा।

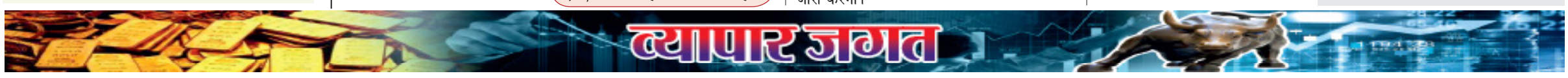

शुरुआती सत्र में बाजार फिसला सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में

एजेंसी । नई दिल्ली

घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को कमजोर संकेतों के साथ कारोबार की शुरुआत की। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित रुझानों और निवेशकों की सतर्कता के कारण शुरुआती बढ़त कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। हालांकि शुरुआती सत्र में आई हल्की खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह मजबूती टिक नहीं पाई और जल्द ही मुनाफावसूली तथा बिकवाली दबाव तेज हो गया। सुबह 10 बजे तक सेंसेक्स 0.41 प्रतिशत गिरकर 85,288 अंक के आसपास पहुंच गया, जबकि निफ्टी 0.38 प्रतिशत टूटकर 26,076 अंक पर कारोबार कर रहा था। आईटी, बैंकिंग और धातु शेयरों में दबाव देखा गया, जबकि एफएमसीजी और फार्मा क्षेत्र में सीमित खरीदारी ने कुछ सहारा दिया।

शेयरों में मिश्रित रुख

लार्ज-कैप शेयरों में एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल 0.38% से 1.11% तक की बढ़त में रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, बजाज फिनसर्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बिकवाली हावी रही, जिससे इनमें 0.36% से 1.25% तक की गिरावट दर्ज हुई।

मार्केट ब्रेड्थ नकारात्मक

सुबह 10 बजे तक कुल 2,059 शेयरों में कारोबार हो रहा था, जिनमें 833 बढ़त में और 1,226 गिरावट में थे। सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयर हरे निशान में और 21 लाल निशान में रहे। निफ्टी के 50 शेयरों में 13 बढ़त और 37 गिरावट में कारोबार कर रहे थे। बीएसई सेंसेक्स ने 316 अंक की कमजोरी के साथ 85,325 पर शुरुआत की थी। शुरुआती लिवाली से सूचकांक ने 200 अंकों से अधिक की रिकवरी भी की, लेकिन 10 मिनट के भीतर बिकवाली बढ़ने से बाजार फिसल गया।

कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच एशियाई बाजारों में मिला–जुला रुख

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक बाजारों से मंगलवार को कमजोर संकेत मिलने के बीच एशियाई शेयर बाजारों में मिश्रित कारोबार देखा जा रहा है। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में पिछले सत्र में बिकवाली हावी रही, जबकि एशिया के कई सूचकांक मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

अमेरिकी बाजारों में गिरावट

अमेरिकी शेयर सूचकांकों की पांच दिन की तेजी थम गई। डाउ जोंस 400 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि एस एंड पी 500 में 0.53% की गिरावट दर्ज की गई और यह 6,812 अंकों पर बंद हुआ। नैस्डैक भी 0.46% गिरकर 23,258 अंक पर आ गया। डाउ जोंस फ्यूचर्स मंगलवार सुबह हल्की तेजी के साथ 0.03% ऊपर कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र में यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में गिरावट हावी रही। एफटीएसई 0.19% तक फिसला, जबकि सीएसी 0.32% गिरा और डीएएक्स में 1.05% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एशिया के 9 में से 6 बाजार हरे निशान में हैं, जबकि 3 सूचकांक निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

रिलायंस रिटेलः कारोबार नई कंपनी को हस्तांतरित

एजेंसी । नई दिल्ली

रिलायंस समूह ने अपने खुदरा कारोबार के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए रिलायंस रिटेल लिमिटेड (आरआरएल) का आंतरिक पुनर्गठन पूरा कर लिया है। कंपनी ने अपने उपभोक्ता उत्पाद कारोबार को नई इकाई न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (न्यू आरसीपीएल) में स्थानांतरित कर दिया है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया गया कि पुनर्गठन के बाद न्यू आरसीपीएल अब सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगी। योजना एक दिसंबर से प्रभावी हो गई है। इस संरचना में आरआईएल की 83.56 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी, जबकि शेष हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास बनी रहेगी।कंपनी के मुताबिक, पुनर्गठन के साथ पुरानी इकाई आरसीपीएल का अस्तित्व समाप्त हो गया है। नई कंपनी के माध्यम से समूह उपभोक्ता उत्पाद कारोबार को अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी रूप में आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेगा। एफएमसीजी सेक्टर में तेजी से पैर जमाने वाली आरसीपीएल ने केवल तीन वर्षों में 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व पार किया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी घटा रही सरकार

एजेंसी । नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी घटाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शेयर बिक्री पेशकश (OFS) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए यह पेशकश मंगलवार को 54 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर खुली, जो बैंक के सोमवार के बंद भाव 57.66 रुपये से करीब 6.34 प्रतिशत कम है। सरकार इस बिक्री से लगभग 2,492 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है। शेयर बिक्री दस्तावेज के अनुसार खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस बुधवार को खुलेगा। आधार प्रस्ताव में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर 38.45 करोड़ शेयर शामिल किए गए हैं, जबकि 'ग्रीन-शू' विकल्प के तहत अतिरिक्त 1 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 7.69 करोड़ शेयर रखने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 6 प्रतिशत हिस्सेदारी, लगभग 46.14 करोड़ शेयर, बाजार में उतारी जाएगी।

79.6 फीसद है सरकार की हिस्सेदारी

फिलहाल सरकार के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79 .60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ओएफएस पूरी होने के बाद सरकारी शेयरधारिता 75 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी, जिससे बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम का पालन करने की स्थिति में आ जाएगा। गौरतलब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा सरकार की हिस्सेदारी चार और बैंकों—इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया—में भी निर्धारित सीमा से अधिक है।

8 दिसंबर को आएगा वेकफिट का आईपीओ

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

घरेलू फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी वेकफिट इनोवेशंस अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को शेयर बाजार में पेश करेगी। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 185-195 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कुल 1,289 करोड़ रुपये के इस इश्यू में 377.18 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि 912 करोड़ रुपये मूल्य के 4,67,54,405 शेयर ऑफ़र फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे इस मिश्रित इश्यू का उद्देश्य कंपनी की पूंजी बढ़ाने के साथ ही मौजूदा निवेशकों को आंशिक निकास का अवसर देना है।

आईपीओ की डेट्स और एंकर बिडिंग

वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ 8 दिसंबर 2025 को निवेशकों के लिए खुलेगा और 10 दिसंबर 2025 को बंद होगा। बड़े यानी एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 5 दिसंबर को ही खुलेगा। माना जाता है कि एंकर इन्वेस्टर्स की शुरुआती प्रतिक्रिया बाजार में खुदरा और संस्थागत निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। बेंगलुरु स्थित वेकफिट इनोवेशंस ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के ऑनलाइन होम फर्निशिंग बाजार में तेज़ी से अपनी जगह बनाई है। कंपनी मैट्रेस, बेड, सोफा, फर्नीचर और होम सॉल्यूशंस जैसी कई कैटेगरी में उत्पाद उपलब्ध कराती है। डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच, डेटा-ड्रिवन डिजाइन और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल ने वेकफिट को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी इस सेक्टर में एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित करने में अहम योगदान दिया है।

फंड्स का इस्तेमाल और कंपनी की रणनीति

वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ से जुटाए गए 377.18 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने विस्तार और संचालन क्षमता बढ़ाने में करेगी। कंपनी इन फंड्स से सप्लाई चेन को मजबूत करेगी, नए वेयरहाउस तैयार करेगी और अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करेगी, ताकि आने वाले वर्षों में वह फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स कैटेगरी में अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी को और मजबूत बना सके। कंपनी के शेयर 15 दिसंबर 2025 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे।

ई-कॉमर्स में उछाल, कंपनियों का लॉजिस्टिक विस्तार

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत के ई-कॉमर्स बाजार में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के महीनों में ऑनलाइन खरीदारी में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और दैनिक उपयोग की श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियाँ वेयरहाउस क्षमता बढ़ाने, डिलीवरी नेटवर्क मजबूत करने और स्वचालित तकनीकों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे मैच

युवा ब्रिगेड से विजय तिलक की उम्मीद

- भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज
- विराट और रोहित पर भी रहेंगी नजरें

एजेंसी । रायपुर

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम बुधवार को सिर्फ दूसरा वनडे नहीं, भारतीय युवा ब्रिगेड की परीक्षा भी देखेगा। नजरें सिर्फ कोहली-रोहित पर नहीं-उन युवाओं पर भी होंगी जिन्हें 2027 विश्व कप की रेस में खुद को साबित करना है। ड्रेसिंग रूम की उथल-पुथल और स्टार खिलाड़ियों के बीच बढ़ती दरार की चर्चाओं के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। रांची वनडे में विराट कोहली के 52वें शतक और रोहित शर्मा की 57 रन की आक्रामक पारी ने को 17 रन से जीत रायपुर में चुनौती की नहीं-संतुलित टीम की पहचान की भी है।

मजबूत होकर उतरेगी दक्षिण अफ्रीका टीम

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की। मार्को यानसेन ने 26 गेंद में अर्धशतक समेत 39 गेंद में 70 रन ठोके। वहीं मैथ्यू ब्रीज्के ने पदार्पण वनडे में 72 रन की पारी खेली। दूसरे वनडे में प्रोटियाज टीम और मजबूत होकर उतरेगी क्योंकि कप्तान तेम्बा बावुमा और केशव महाराज की वापसी उसकी गेंदबाजी-बल्लेबाजी की धुरी को और संतुलित करेगी।

टीम की चिंताएं

पहले वनडे की जीत के बावजूद टीम की चिंताएं कई हैं। रुतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर भेजा गया लेकिन वह सहज नहीं दिखे। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे और टीम का बैटिंग ऑर्डर लगातार प्रयोगों से गुजरता रहा। वॉशिंगटन सुंदर भी इस 'मल्टी-रोल' से अछूते नहीं हैं। कोलकाता टेस्ट में नंबर तीन और अब वनडे में नंबर पांच, पर बड़ी पारी नहीं निकल सकी। गेंदबाजी में उनसे सिर्फ तीन ओवर ही कराए गए जिसमें 18 रन लुटे। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने नई गेंद से दो विकेट जरूर लिए, लेकिन डेथ ओवर्स में रन बह गए। खासकर तब जब 34वें ओवर के बाद आईसीसी के नए नियम के तहत सिर्फ एक ही सफेद गेंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम ने बल्ले-बॉल का संतुलन और संवेदनशील बना दिया है। कुलदीप यादव ने 68 रन देकर चार विकेट चटकाए। वह महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उनकी विविधता ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी वापसी नहीं करने दी।

रायपुर में पिच का मिजाज कैसा होगा?

केएल राहुल की अगवाई वाले भारतीय टीम और तेंबा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी। इस मैदान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां बल्ले और गेंद के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलती है। शुरुआत में यहां के मैदान पर बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलता है!

रायपुर की पिच के आंकड़े कैसे हैं?

रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में अब तक सिर्फ एक वनडे मुकाबला ही खेला गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2023 में आखरी बार इस फॉर्मेट में मैच हुआ था। उस मुकाबले में भी कीवी टीम सिर्फ 108 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। 109 रनों के लक्ष्य को भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 20. ओवर में पूरा कर लिया था।

पीठ की चोट ने रोका उस्मान ख्वाजा का सफर

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया को एशेज श्रृंखला के दूसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा पीठ की चोट के चलते ब्रिस्बेन में होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। टीम मैनेजमेंट ने मंगलवार को उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला लेते हुए उन्हें आराम देने का निर्णय लिया।

पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान ख्वाजा को पीठ में तेज ऐंठन हुई थी, जिसके कारण वे दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। सोमवार को गाबा में अभ्यास के दौरान भी उन्हें असहजता महसूस हुई, जिसके बाद टीम चिकित्सकों ने उन्हें अगले मैच के लिए फिट न मानते हुए बाहर कर दिया। तेज गेंदबाज़ स्कॉट बोलैंड ने कहा, "उन्होंने पिछले मैच के बाद से लगातार अपनी फिटनेस पर काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे पूरी तरह तैयार नहीं हो सके। नेट्स में वे बेहतर दिख रहे थे, लेकिन लगता है कि वे खुद भी मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे।"

ख्वाजा के बाहर होने के बाद किसी नए खिलाड़ी को टीम में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में पर्थ टेस्ट में शानदार 123 रन की पारी खेलने वाले ट्रैविस हेड के एक बार फिर ओपनिंग करने की संभावना बढ़ गई है।

ECA 2026 में शुरू करेगा यूरो टी20 क्लब चैंपियंस ट्रॉफी

- महाद्वीप के शीर्ष क्लबों को मिलेगा साझा मंच

इस्तांबुल। यूरोपियन क्रिकेट एसोसिएशन (ईसीए) ने 2026 से नए टी20 क्लब टूर्नामेंट—यूरो टी20 क्लब चैंपियंस ट्रॉफी—की शुरुआत की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता महाद्वीप के राष्ट्रीय चैंपियन क्लबों को एक ही मंच पर मुकाबले का अवसर देगी। इस्तांबुल में हुई वार्षिक कांग्रेस के दौरान ईसीए ने सदस्य देशों से मेजबानी के प्रस्ताव 31 जनवरी 2026 तक भेजने को कहा है। आयोजन स्थल का अंतिम चयन फरवरी में किया जाएगा।

नया नेतृत्व चुना गया

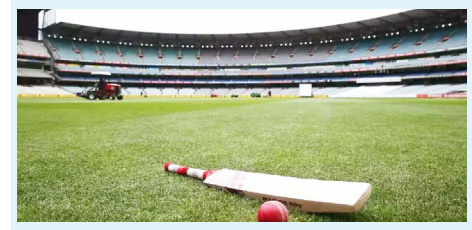

सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित चुनाव में रोमानिया के गैब्रिएल मारिन को ईसीए का नया अध्यक्ष चुना गया। नॉर्वे के यूसुफ गिलानी को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि गुरुमूर्ति पलानी (फ्रांस), मोहम्मद बिलाल ज़लमानी (ऑस्ट्रिया) और इंडिका थिलन परेरा (माल्टा) उपाध्यक्ष पद पर चुने गए। संस्था के संविधान के अनुरूप बोर्ड का विस्तार कर 11 सदस्यों तक किया गया।

आने वाले वर्षों की रूपरेखा तैयार

ईसीए ने टी10 क्रिकेट के बढ़ते वैश्विक बाज़ार को देखते हुए बताया कि 2026 में टी10 इवेंट्स की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मार्केटिंग और प्रतियोगिता आयोग इसकी विस्तृत सिफारिशें अगले वर्ष कार्यकारी समिति के सामने रखेगा। ईसीए ने अगले चार वर्षों के शासन ढांचे को मंजूरी देते हुए तीन वर्ष की प्रतियोगी योजना भी जारी की। इसमें पुरुष एवं महिला यूरोपीय चैंपियनशिप के साथ अंडर-19 यूरोपियन चैम्पियनशिप को प्राथमिकता दी गई है।

जमीनी स्तर पर मजबूती पर जोर

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और क्रिकेट को शिक्षा तथा सामाजिक समावेशन का माध्यम बनाने के लिए विशेष पहल की जाएंगी। अध्यक्ष मारिन ने कहा, "हमने आगामी वर्षों के लिए अपनी रणनीतिक दिशा तय कर ली है। लक्ष्य है कि क्रिकेट को यूरोप में स्थायी और प्रभावी रूप से स्थापित किया जाए।"

ग्लेन मैक्सवेल ने IPL ऑक्शन से हटाया नाम

- इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी फैसले की जानकारी

एजेंसी । नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अगले सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की नीलामी से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी एक भावुक संदेश में उन्होंने इसकी पुष्टि की। मैक्सवेल पिछली नीलामी में पंजाब किंग्स द्वारा 4.2 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे, लेकिन आईपीएल 2025 उनके लिए निराशाजनक रहा।

सीजन के दौरान वे फॉर्म हासिल नहीं कर सके—9 मैचों में केवल 78 रन और 4 विकेट ही उनके खाते में आए। चोट ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाईं और मध्य उंगली में फ्रैक्चर होने के बाद उन्हें टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा। 2012 में आईपीएल डेब्यू करने वाले मैक्सवेल कई सीजन में चमके। 2014 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला जब उन्होंने 542 रन बनाए। इसके बाद 2017, 2021, 2022 और 2023 में भी उन्होंने अहम पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की।

आईपीएल से भावनात्मक रिश्ता : मैक्सवेल

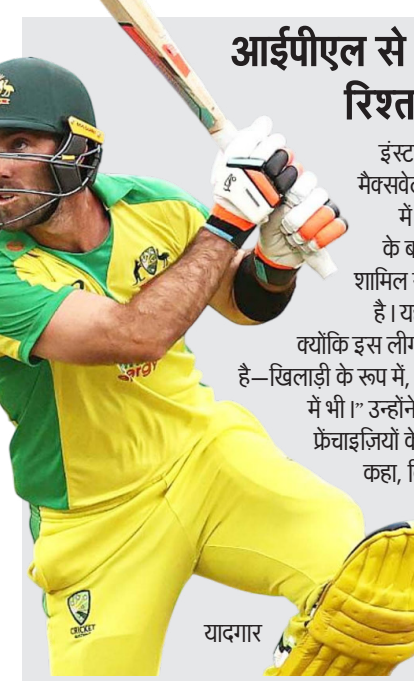

यादगार

इंस्टाग्राम पर अपने संदेश में मैक्सवेल ने लिखा, "आईपीएल में बिताए गए शानदार वर्षों के बाद, इस बार ऑक्शन में शामिल न होने का फैसला लिया है। यह निर्णय भावनात्मक है, क्योंकि इस लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया है—खिलाड़ी के रूप में, और एक इंसान के रूप में भी।" उन्होंने भारतीय प्रशंसकों और फ्रेंचाइज़ियों के प्रति आभार जताते हुए कहा, विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने और भारतीय दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का अनुभव हमेशा रहेगा।

न्यूज ब्रीफ

सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला शतक मंगलवार को कोलकाता में बिहार और महाराष्ट्र के बीच ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान बनाया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने ऐसा करने के लिए 58 गेंदें लीं, जिसमें सात चौके और इतने ही छक्के मारे। उनके नाम पहले से ही सबसे कम उम्र के टी20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीज़न में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। सूर्यवंशी ने पहले 34 गेंदों पर टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक बनाया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज 61 गेंदों पर 108 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे बिहार ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन बनाए।

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल ड्रॉ में शामिल होंगे राष्ट्रपति ट्रंप

वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी शुक्रवार को राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रॉ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रतिष्ठित कैनेडी सेंटर में होने वाले इस समारोह में दुनिया भर की नजरें होंगी। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से 2026 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस आयोजन को अपने दूसरे कार्यकाल की प्राथमिक योजनाओं में शामिल कर चुके हैं और इसे अगले वर्ष अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के प्रमुख आकर्षणों में से एक मानते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल ड्रॉ में भाग लेंगे।

विश्व कप के लिए विनीसियस को चाहिए पूर्ण फिटनेस

नई दिल्ली। ब्राज़ील फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने स्पष्ट कहा है कि स्टार फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर को 2026 फीफा विश्व कप टीम में स्थान पाने के लिए पूरी तरह फिट होकर मैदान में उतरना होगा। कोच ने दोहराया कि वे किसी भी खिलाड़ी को तभी चुनेंगे जब वह 100 प्रतिशत फिट हो। एंचेलोटी इससे पहले नेमार को भी इसी तरह की हिदायत दे चुके हैं कि राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए उन्हें पूरी फिटनेस के साथ लौटना होगा। ईस्पोर्ट्स रिकॉर्ड को दिए इंटरव्यू में एंचेलोटी ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसा मानक लागू होता है। उन्होंने कहा, "मेरी टीम में कई शानदार खिलाड़ी हैं। चयन उन्हीं का होगा जो पूरी तरह फिट हों। यह सिर्फ नेमार नहीं, विनीसियस पर भी लागू होता है। अगर विनीसियस 90% फिट हैं और दूसरा खिलाड़ी 100% फिट है, तो मैं 100% फिट खिलाड़ी को ही चुनूंगा।

बॉलीवुड

'द राजा साब' में बोमन ईरानी का दमदार लुक आया सामने

भारत की सबसे बड़ी हॉरर-फैंटेसी फिल्म 'द राजा साब' के निर्माताओं ने बोमन ईरानी के जन्मदिन को वाकई एक सिनेमाई उत्सव में बदल दिया। टीम ने इस खास मौके पर अभिनेता का नया लुक पोस्टर रिलीज़ किया, जिसने सोशल मीडिया पर जोरदार हलचल मचा दी और इंडस्ट्री में उत्सुकता को और बढ़ा दिया। फिल्म में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के किरदार में दिखाई देंगे। उनका चरित्र बुद्धि, रहस्य और अलौकिक दुनिया की खोज इन तीनों का अनोखा संगम पेश करता है। जन्मदिन पर जारी किया गया यह स्पेशल पोस्टर फिल्म के मनोवैज्ञानिक पहलू की सबसे मजबूत झलक पेश करता है। गहरे रंगों की पृष्ठभूमि में, हाथ में छड़ी लिए बोमन ईरानी का यह रूप ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनदेखी, रहस्यमयी दुनिया की परतों में गहराई तक उतर चुके हों। मेकर्स ने इस अवसर पर बोमन ईरानी के लिए एक खास संदेश भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, जो हकीकत और अनजाने के बीच खड़ा है टीम 'द राजा साब' की ओर से बोमन ईरानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने भी उन्हें बधाई देते हुए लिखा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बोमन ईरानी सर, आने वाला साल शानदार हो। प्रभास की करिश्माई मौजूदगी और बोमन ईरानी की गहरी, बौद्धिक गंभीरता के साथ 'द राजा साब' अब 2026 की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो चुकी है। बोमन का यह बर्थडे पोस्टर फिल्म के रहस्यों की पहली आधिकारिक दस्तक माना जा रहा है।

'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जी ले ज़रा' एक बार फिर चर्चा में है। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट स्टारर इस महिला प्रधान रोड-ट्रिप फिल्म को लेकर लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि यह बंद हो चुकी है। लेकिन हालिया बातचीत में निर्देशक फरहान अख्तर ने सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, फरहान अख्तर ने साफ कहा है कि 'जी ले ज़रा' बिल्कुल बंद नहीं हुई है। फिल्म एक्टिव है, पिछली शेड्यूलिंग समस्याओं के चलते इसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया था। फरहान इससे पहले 'डॉन 3' को लेकर भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह प्रोजेक्ट भी बंद नहीं हुआ है। फिल्म की घोषणा कई साल पहले हुई थी, लेकिन लगातार बाधाओं के कारण शूटिंग शुरू नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती मैरी के जन्म के बाद फिल्म छोड़ने पर विचार किया था। इसके बाद अनुष्का शेट्टी को कास्ट किए जाने की खबरें आईं। कैटरीना कैफ भी अपनी

अन्य कमिटमेंट्स के कारण प्रोजेक्ट से बाहर होने की चर्चा में थीं। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि 'जी ले ज़रा' अपने मूल स्टारकास्ट प्रियंका, कैटरीना और आलिया के साथ ही आगे बढ़ेगी। लगातार खिंचते शेड्यूल और अफवाहों के बीच अब यह पुष्टि होना फैंस के लिए राहत की बात है कि फिल्म को लेकर तैयारियां फिर से पटरियों पर आ रही हैं।

रणवीर सिंह ने 'कांतारा' विवाद पर मांगी माफी

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हाल ही में अपनी एक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आईएफएफआई 2025 के समापन समारोह के दौरान उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए किरदार का अभिनय दोहराया था। समारोह का वीडियो वायरल होते ही कई लोगों ने रणवीर पर देवी चामुंडादेवी का अपमान करने का आरोप लगाया। हिंदू जनजागृति समिति ने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई। बढ़ते विवाद को देखते हुए अभिनेता ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए माफी मांगी है।

रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ₹मेरा इरादा ऋषभ शेट्टी के अद्भुत अभिनय की सराहना करने का था। मैं जानता हूं कि उन्होंने उस दृश्य को कितनी मेहनत और समर्पण से निभाया है, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हमेशा देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान किया है। यदि मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।

विवाद की शुरुआतगोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रणवीर ने 'कांतारा चैप्टर 1' पर बात करते हुए कहा था, मैंने कांतारा चैप्टर 1 देखी। ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस शानदार थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत आता है, तो आपने कमाल का शॉट दिया। उनकी इसी टिप्पणी को कई लोगों ने धार्मिक आस्था से जोड़कर आपत्तिजनक बताया। फिलहाल, रणवीर अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 5 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रही है।

'धुरंधर' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी

रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' को आखिरकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से हरी झंडी मिल गई है। 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को लेकर चल रही बाधा अब दूर हो चुकी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। सेंसर बोर्ड का निर्णय निर्माताओं के लिए बड़ी राहत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने 'धुरंधर' को एक 'काल्पनिक कृति' (फिक्शन फिल्म) बताते हुए पास किया है। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि फिल्म का दिवंगत मेजर मोहित शर्मा की वास्तविक जिंदगी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि फिल्म को अतिरिक्त जांच के लिए भारतीय सेना के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार उनके बेटे की जिंदगी से प्रेरित प्रतीत होता है, वह भी बिना अनुमति। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि सीबीएफसी फिल्म को प्रमाणपत्र देने से पहले पुनः जांच करे।

मोबाइल की सुरक्षा का साथी या जासूसी!

- संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा
- सरकार जासूसी करना चाहती है : प्रियंका गांधी
- सरकार का यू टर्न, पहले कहा था- सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा; आज बोली- डिलीट कर सकते हैं

एजेंसी । नई दिल्ली

सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' को प्री-इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग (DoT) के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी एप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐप के जरिए फोन इस्तेमाल की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है। उन्होंने कहा कि यह नागरिक की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी ने भी संचार साथी ऐप को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जासूसी के लिए सरकार किस हद तक जाना चाहती है। पार्टी ने इसे तानाशाही की ओर कदम करार देते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

फ्रॉड रोकने का नया टूल मान रही सरकार

केंद्र सरकार ने सोमवार को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। आदेश में एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस एप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह एप इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। सरकार का कहना है कि एप चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकने के काम

संचार साथी ऐप और पोर्टल की अब तक की उपलब्धियां

- 21.5 करोड़ से अधिक पोर्टल विजिट
- 1.4 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड
- 1.43 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट नागरिकों द्वारा 'नॉट माय नंबर' चुनने पर
- 26 लाख खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस, इनमें से 7.23 लाख फोन वापस लौटाए गए

एपल अपने फोन में संचार एप प्री-इंस्टॉल नहीं करेगा

अमेरिकी टेक कंपनी एपल भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें हर नए फोन में 'संचार साथी' एप इंस्टॉल करने को कहा गया है। मंगलवार (2 दिसंबर) को पीटीआई ने रिपोर्ट में बताया कि, एपल इस फैसले से सहमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह संचार साथी एप और पोर्टल यूजर्स के सिम कार्ड्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एपल इसे प्राइवेसी में दखल मान रही है। कंपनी का कहना है कि, 'आदेश पर सरकार के साथ बातचीत की जाएगी और बीच का रास्ता निकालेंगे। हम मौजूदा स्वरूप में आदेश लागू करने में सक्षम नहीं है।' संचार विभाग ने मई 2023 में संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की। इसके बाद 17 जनवरी 2024 से संचार साथी ऐप को भी लॉन्च किया गया, ताकि मोबाइल उपयोगकर्ता फर्जी नंबर, चोरी/खोए फोन और साइबर फ्रॉड की शिकायत आसानी से कर सकें।

परमाणु ऊर्जा, SU-57 और S-400 सौदे पर समझौता संभव

- भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन

एजेंसी । नई दिल्ली

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों की संभावना जताई जा रही है। यात्रा के एजेंडे में पाँचवीं पीढ़ी के सुखोई-57 लड़ाकू विमानों, एस-400 हवाई सुरक्षा प्रणाली की खरीद, जेट इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और छोटे परमाणु संयंत्रों की स्थापना शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देश अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किसी फार्मूले पर सहमति बनाने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध केवल औपचारिक व्यापार समझौतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह ऐतिहासिक साझेदारी, वैश्विक मामलों में साझा दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान पर आधारित हैं।

रक्षा और ऊर्जा सहयोग

पेस्कोव ने बताया कि यात्रा के दौरान एसयू-57 स्टेल्थ फाइटर विमान और एस-400 लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भारत में छोटे परमाणु रिएक्टरों की स्थापना और कुडनकुलम में असैन्य परमाणु संयंत्र परियोजनाओं में रूस की भागीदारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "रूस के पास छोटे और लचीले रिएक्टरों का व्यापक अनुभव है। यह सहयोग भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

व्यापारिक और आर्थिक सहयोग

पेस्कोव ने उल्लेख किया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के अधिकारी व्यापारिक ढांचे में बदलाव और सुधार के तरीकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और आतंकवाद

रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पेस्कोव ने कहा कि रूस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का सम्मान करता है और युद्ध के समाधान के लिए अमेरिका की योजना का भी समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोटों की निंदा की जाती है।

न्यूज़ ब्रीफ

मणिपुर माल और सेवा कर विधेयक पर संसद की मुहर

नई दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जो इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। सदन में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के शोर-शराबे के बीच इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सीतारमण ने बताया कि यह विधेयक मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे सात अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था।

अमेजन नदी में दो नावें डूबीं, 12 की मौत

लीमा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में अमेजन नदी के पास सोमवार को अचानक भूस्खलन होने दो नावें आपस में टकराने के बाद डूब गईं। इस हादसे में कम से कम तीन बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा नदी के तटीय उकायाली क्षेत्र में हुआ।

ग्राउंड न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से संचालित एक समाचार एजेंसी ने कहा कि पेरू के पुलिस विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इन दो यात्री नावों में चिकित्सक और कई आदिवासी परिवार सवार थे। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग लापता हैं। पेरू के राष्ट्रीय आपात केंद्र ने कहा कि राहत और बचाव अभियान में हेलिकॉप्टर को शामिल किया है।

इस साल 53 पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा : बीएसएफ

मोहाली। बीएसएफ ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के उन हॉटस्पॉट्स की पहचान कर ली है, जिनका इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता है। साथ ही इस साल 278 'रोग' ड्रोन और 53 पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। यह जानकारी बीएसएफ वेस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश एस. खंदारे ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि पंजाब और जम्मू में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि ड्रोन घुसपैठ रोकी जा सके। जम्मू में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी-टनलिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। खंदारे ने बताया कि इस वर्ष बीएसएफ वेस्टर्न कमांड ने 380 किलो से अधिक हेरोइन, 200 से ज्यादा हथियार, बरामद करने के साथ 278 'रोग' ड्रोन और 53 पाकिस्तानी घुसपैठियों व तस्करों को पकड़ा है। बीएसएफ ने अमृतसर में ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की है, जहां ड्रोन की उड़ान, रूट और डिलीवरी पॉइंट का पता लगाने के लिए उसकी जांच की जाती है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाली यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू

एजेंसी । काठमांडू

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अब नेपाली यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष सूचना सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है। दिल्ली होकर विदेश यात्रा करने वाले नेपाली नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा ने बताया कि इस नई सुविधा का उद्देश्य ट्रांजिट प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाना है। हाल के दिनों में फर्जी वीज़ा, एनओसी और अन्य दस्तावेज़ों की वजह से कई यात्री परेशानी में पड़ रहे थे, जिसे देखते हुए दूतावास और एयरपोर्ट प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह व्यवस्था की है। दूतावास ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि ट्रांजिट या सुरक्षा जांच के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। यह कदम विशेष रूप से उस घटना के बाद उठाया गया है, जब दो अलग-अलग उड़ानों से चार नेपाली महिलाओं को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। इस मामले ने यूरोप और अमेरिका जाने वाले नेपाली यात्रियों में चिंता बढ़ा दी थी। मामले के बाद नेपाली दूतावास ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क कर यात्रियों की सुरक्षा और दस्तावेज़ जांच की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया था।

ट्रांजिट प्रक्रिया होगी और आसान

संसद में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा

एजेंसी । नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल जारी रखा, लेकिन हंगामा थमता नहीं देखा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा के लिए विषय और सदस्यों के नाम बताने की परंपरा है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर चर्चा टालने का आरोप लगाया। वहीं, सभापति ने कहा कि मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और बाद में प्रतिक्रिया देंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने बताया कि मंत्री रिजिजू विपक्षी नेताओं के साथ जल्द बैठक करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी दोनों सदनों की कार्यवाही

लोकसभा में भी हंगामा जारी

लोकसभा में भी स्थिति कम नहीं रही। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जीतिन प्रसाद के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने आए, तो विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप वेल में पहुंच गए और हंगामा जारी रखा। रिजिजू ने बार-बार विपक्ष को शांत रहने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन हंगामा थमता नहीं देखा गया।

रेणुका प्रकरण पर कन्नी काट गए राहुल गांधी

कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी के सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में कुत्ते को लेकर आने और उनकी विवादित टिप्पणी पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि ये वे चीजें हैं जिन पर भारत इन दिनों चर्चा कर रहा है? उस कुत्ते ने क्या किया? क्या यहां कुत्तों की अनुमति नहीं है? शायद यहां पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है।" उल्लेखनीय है कि कुत्ता प्रकरण पर विवाद बढ़ने पर अपनी सफाई में सांसद रेणुका चौधरी ने कहा था कि सड़क पर एक छोटा पिल्ला स्कूटर और कार की टक्कर के रास्ते में था। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि उसे टक्कर लग जाएगी। इसलिए मैंने उसे उठाया, कार में बिठाया, संसद आई और वापस भेज दिया। कार चली गई और कुत्ता भी।"

लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार बाधित होने के बाद दोपहर दो बजे पुन: शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामे के कारण सिर्फ पांच मिनट में ही कार्यवाही अगले दिन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे शांत होकर बैठें और सदन में चर्चा चलने दें। उन्होंने कहा कि देश की जनता सदन की कार्यवाही देख रही है और अपने मुद्दों की चर्चा सुनना चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर बार-बार सदन को बाधित करने और वेल में हंगामा न करने की अपील करते हुए इसे जनता के लिए नुकसानदायक बताया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सिर्फ पांच मिनट के भीतर यानी दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही अगले दिन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

बंदरगाह से बाहर निकली पाक की नौसेना: एडमिरल त्रिपाठी

- वार्षिक प्रेस कांफ्रेंस में दिनेश के त्रिपाठी ने ऑपरेशन 'सिंदूर' का किया जिक्र

एजेंसी । नई दिल्ली

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा है कि ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान भारतीय नौसेना की त्वरित और आक्रामक कार्रवाई ने पाकिस्तान को इतना दबाव में ला दिया कि उसकी नौसैनिक इकाइयाँ बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैरियर बैटल ग्रुप की समयबद्ध तैनाती ने स्थिति को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2029 तक भारतीय नौसेना को फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर गंभीर प्रदूषण की चपेट में, एक्यूआई 'बेहद खराब' दर्ज

एजेंसी । नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चेतावनी की घंटी बजा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 372 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ठंडी हवाओं की कमी, तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं।

चांदनी चौक में सांस लेना भी मुश्किल

20.45 फीसद प्रदूषण वाहनों से

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई 0-50: अच्छा, 51-100: संतोषजनक, 101-200: मध्यम, 201-300: खराब, 301-400: बेहद खराब, 401-500: गंभीर माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहन यातायात है, जो कुल प्रदूषण का 20.45 फीसदी योगदान देता है। इसके अलावा पराली जलाने का हिस्सा 1.97 फीसदी, निर्माण एवं ध्वंस गतिविधियों का 3.10 फीसदी और आवासीय क्षेत्रों का 5.30 फीसदी है।

प्रभावित इलाके

नई दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक: औसत एक्यूआई 450 ('गंभीर'), बवाना: औसत एक्यूआई 415, आनंद विहार: औसत एक्यूआई 408, पंजाबी बाग: औसत एक्यूआई 392, आईटीओ: औसत एक्यूआई 379, शादीपुर: एक्यूआई 374, द्वारका सेक्टर-8: एक्यूआई 356, दिलशाद गार्डन: एक्यूआई 342 के अलावा एनसीआर के गाजियाबाद: औसत एक्यूआई 361, ग्रेटर नोएडा: 378, हापुड़: 379, बहादुरगढ़: 306 और चरखी दादरी: 305 दर्ज की गई।

साइबर सुरक्षा के लिए IIT कानपुर और NMDC ने मिलाया हाथ

एजेंसी । कानपुर

आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी लिमिटेड ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य एनएमडीसी के आईटी और ओटी सिस्टम्स को मजबूत बनाना और साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में नई पहल करना है। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि संस्थान का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा और एआई की चुनौतियों को संभालने में बेहद मूल्यवान है।

सिक्योरिटी आपरेशंस सेंटर का माडल होगा मजबूत

एमओयू के तहत आईआईटी कानपुर का सीआईहब एनएमडीसी को साइबर रिस्क असेसमेंट, सुरक्षा खामियों की पहचान, सुरक्षा प्रबंधन, घटना प्रतिक्रिया योजना और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर के मॉडल को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा, दोनों संस्थान मिलकर अनुसंधान, क्षमता निर्माण और तकनीकी पायलट परियोजनाएं भी चलाएंगे, जिनके सफल परिणामों को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या घुसपैठियों पर जताई गंभीर चिंता

'क्या हम रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करें?'

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों की हिरासत में कथित गायब होने की याचिका पर सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कड़ा सवाल किया कि क्या वे चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाकर स्वागत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लिया था और तब से उनका कोई पता नहीं है।

अवैध घुसपैठ संवेदनशील प्रकरण

याचिका रीता मनचंदा ने दायर की है, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संवेदनशील बताते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और शरणार्थी मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक कल्याण दोनों पक्षों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुनवाई केवल रोहिंग्या घुसपैठियों की कानूनी स्थिति का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे देश की शरणार्थी नीति, नागरिक अधिकार और सुरक्षा ढांचे पर भी बहस छिड़ सकती है।

सरकार ने शरणार्थी का दर्जा दिया?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह समझना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने के बावजूद वे खाद्य, आवास और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के हकदार कैसे बन जाते हैं, जबकि हमारे अपने देश में भी अनेक गरीब लोग हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या अवैध घुसपैठियों को विशेष सुविधाएं देकर स्थानीय नागरिकों के अधिकारों पर असर डाला जाना चाहिए।